सम्पादकीय

किसानों की पुकार अनसुनी, आंदोलन के बीच जीवन-मौत का संघर्ष क्यों?

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है, उसके मुद्दे स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा ठोस कदम उठाने के प्रति उदासीन दिख रही है, जो एक समाधान की राह तक पहुंचे। क्या यह साफतौर पर सरकार के भीतर राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव को प्रदर्शित नहीं करता कि वह किसानों की मांग को लेकर इस हद तक अगंभीर दिख रही है कि आंदोलन के एक नेता की सेहत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है, उनके जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है और वह हल के लिए सहमति बनाने के बजाय समस्या की अनदेखी करने में लगी है।

सवाल है कि आखिर किन वजहों से वह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानूनी गारंटी पर स्थिति स्पष्ट नहीं करना चाहती है और उसका यह रुख किसके हित में है। गौरतलब है कि एक ओर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले पैंतालीस दिनों से अनशन पर हैं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है, दूसरी ओर, इसी मसले पर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने की वजह से बीते तीन हफ्ते के भीतर दो किसानों ने आत्महत्या कर ली। यह समझना मुश्किल है कि एक लोकतांत्रिक सरकार इस हद तक उदासीन कैसे हो सकती है कि अपनी समस्याओं की अनदेखी किए जाने की वजह से किसानों के जान देने की खबरें आ रही हैं, वहीं उनके नेता का जीवन भी जोखिम में है। अगर किसानों के संगठित आंदोलन के सामने ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात पैदा हो रहे हैं, तो बाकी मसलों के संदर्भ में अंदाजा लगाया जा सकता है। डल्लेवाल के अनशन और उनकी सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। मगर इसके बावजूद सरकार कोई ऐसी राह तलाशने को लेकर उत्सुक नहीं दिख रही है, जिससे किसान आंदोलन की मांगों पर सभी पक्षों के बीच कोई सहमति कायम हो सके और डल्लेवाल अपना अनशन फिलहाल खत्म करें। अगर सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किए जाने के मसले पर ईमानदार है तो वह इस संबंध में कानूनी गारंटी का प्रावधान करने से क्यों हिचक रही है? जबकि खुद एक संसदीय समिति भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की वकालत कर चुकी है।

मौजूदा दौर में खेती-किसानी के सामने बढ़ती चुनौतियां किसी से छिपी नहीं है। बाजार के बदलते ढांचे के बीच किसानों की बढ़ती समस्याओं को दूर करने के मकसद से नीतिगत पहल करना सरकार को जरूरी नहीं लगता। उल्टे जिस तरह की व्यवस्था से किसान अपनी असहमति जताते हैं, भविष्य में उसके घातक परिणाम बताते हैं, सरकार को उस ओर कदम बढ़ाने में कोई हिचक नहीं होती। पिछली बार किसानों के कई महीने चले आंदोलन के बाद सरकार को विवश होकर विवादित तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। तब यह उम्मीद की गई थी कि अब सरकार किसानों के साथ मिल-बैठ कर इस समस्या पर सहमति के बिंदुओं की तलाश करेगी और कोई ठोस हल उभर कर सामने आएगा। मगर यह अफसोस की बात है कि किसानों को अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और सरकार ने लगातार टालमटोल का रवैया अख्तियार किया हुआ है। सरकार और किसानों के बीच चल रही यह खींचतान की स्थिति अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरकार को चाहिए कि वह समय रहते इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस पहल करे।

आज का राशिफल

हमारे अनुसार अठारहवीं तारीख के अनुसार आप कई विधियां लगाते रहे हुए करोगे। तब आप यह समझना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपको विशेष ध्यान देना और उसमें सुधार करने, आपको किस बातों से लाभ होगा। इस में किसी सम्बन्धी व्यक्ति में और महीना कुछ को तुलनात्मक रूप से समझना जरूरी होगा, क्योंकि पंचमहाविध तत्वों के भी, जब यह लाभकारक नहीं लगता और बताता है तब प्रयास करेंगे

मेष
आज रिश्तेदार एवं मित्रों के साथ मुलाकात से आप आनंद का अनुभव करेंगे। आपको पहले थोड़ी मुसीबत हो सकती है, आपके जरूरी काम भी शुरुआती विलंब के बाद आसानी से पूरे होने पर शांति का अहसास करेंगे।

वृष
काम का बोझ ज्यादा रहेगा। नए काम की शुरुआत न करें। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा। वाणी पर संयम रखें। आज आपका दिन शुभ है। व्यापार बढ़ाने को लेकर आपके प्रयास रंग लाएंगे।

मिथुन
आज आपको काफी संवेदनशीलता का अनुभव होगा। इस कारण किसी के द्वारा आपकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। आज आपको मां की बीमारी की चिंता होगी। मकान या जमीन के दस्तावेजी काम आज न करें।

कर्क
महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान रखें। वाणी एवं व्यवहार में सावधानी बरतें। विदेश से कोई समाचार मिल सकता है। कानूनी बातों का निर्णय सोच-समझकर करें। आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आको लाभ होगा।

सिंह
मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे। धनप्राप्ति के लिए भी शुभ समय है। अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिलेगी।

कन्या
मानसिक व्यग्रता को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता, योग का सहारा लें। महिला और पानी से बचकर रहें। अभ्यास के लिए समय मध्यम है। आज आप को ज्यादा संवेदनशील एवं भावुकता भरे विचार आएंगे। इससे आपका मन द्रवित हो उठेगा।

तुला
दूसरों की ओर से चिंता कम होगी। इस कारण आप का मन खुश रहेगा। परिजनों या दोस्तों के साथ अच्छे भोजन का अवसर मिलेगा। कोई आकस्मिक यात्रा हो सकती है। आर्थिक मामलों से संबंधित व्यवस्था कर सकेंगे।

वृश्चिक
प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे। पत्नी के संग से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों के लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा।

धनु
अधिकारियों का रवैया नकारात्मक रहेगा। विरोधियों के साथ वाद-विवाद न करें। संतान से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा की संभावना है। धनखर्च होगा। कार्य सफलता में विलंब होने के कारण निराशा का अनुभव होगा।

मकर
आज आप के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आप पर अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। परिवार में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहेगा। मन में भावनात्मकता बढ़ेगी। मां की ओर से फायदा होगा।

कुंभ
अनुकूल वातावरण रहेगा और साथियों का सहयोग मिलेगा। आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे। दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। आप उनके साथ अपना दिन खुशी में गुजार सकेंगे।

मीन
जमीन-जायदाद के दस्तावेजी काम कर सकेंगे। आपका आज का दिन प्रतिकूलताओं एवं अनुकूलताओं से भरा होगा। लेखन-साहित्य से जुड़े काम कर सकेंगे। होलांकि, व्यवसायिक स्थल पर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी। काम समय से पूरा नहीं होगा।

आज का इतिहास
बढ़ता राजस्थान

11 जनवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- पहली लाटरी का शुभारम्भ 1569 में इंग्लैण्ड में हुआ।
- मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत 1613 में दी।
- ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से 1616 में मुलाकात की।
- ब्रैडेनबर्ग और फ्रांस के बीच 1681 में रक्षा गठबंधन हुआ।
- स्पेन नरेश जोकिन मुरात ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ 1753 में छोड़ दिया।
- 1759 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली जीवन बीमा कंपनी की शुरूआत।
- चिंग थांग खौंबा मणिपुर के राजा 1779 में बने।
- डायबटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन 1922 में दी गई थी।
- जापान ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर 1942 में कब्जा किया।
- यूनानी गृहयुद्ध में संघर्ष विराम 1945 में हुआ।
- भारत के अखबारी कागज का उत्पादन 1955 में प्रारम्भ हुआ।
- 1962 में हिमस्खलन से पेरुवियन एंडेस गाँव में तीन हज़ार मौतें हुईं।
- सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्धविराम का उल्लंघन करने के लिए 1993 में चेतावनी दी।
- सोमालिया में दो वर्ष से चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियान 1995 में समाप्त।
- जॉर्डन के शाह हुसैन 1996 में अपनी पहली सार्वजनिक यात्रा पर इजरायल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पहुंचे।
- लुईस फ्रेचेट (कनाडा) 1998 में सं.रा. संघ की उपमहासचिव नियुक्त।
- भारत और इंडोनेशिया के बीच 2001 में पहली बार रक्षा समझौता।
- रिलायंस ने बी.एस.एन.एल. को 2005 में 84 करोड़ रुपये चुकाए।
- 2009 में हुए 66 वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में स्लमडॉग मिलियनेयर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।
- सोमालिया के बुल्ली मारेर में एक फ्रांसिसी बंधक को छुड़ाने के प्रयास में 2013 में फ्रांस के एक सैनिक की मौत। इस दौरान 17 आतंकवादी भी मारे गये।

11 जनवरी को जन्मे व्यक्ति

- भारतीय राजनीतिज्ञ शिबु सोरेन का जन्म 1944 में हुआ।
- बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म 1954 में हुआ।
- भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक का जन्म 1860 में हुआ।
- प्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का जन्म 1842 में हुआ।

विशेष आलेख

बेमेल के इंडिया गठबंधन को बिखरना एवं टूटना ही था

✍ ललित गर्ग

इनदिनों बिहार और दिल्ली में सियासी पारा कड़ाके की ठंड में भी गर्म है। वजह है कि दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है एवं साल के अंत तक बिहार में कौन राज करेगा इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले दिल्ली एवं बिहार में राजनीतिक सरगर्मियों एवं तीखी बयानबाजी के बाद इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया। दिल्ली चुनाव में 'आप' और कांग्रेस के बीच की दूरी और सहयोगी दलों के रुख के बाद गठबंधन की टूट तय हो गयी है और इस बात की पुष्टि गठबंधन के नेताओं से बयानों से हो रही है। वैसे तो इंडिया गठबंधन की नाव कांग्रेस के हरियाणा और महाराष्ट्र में हारने के बाद ही हिचकोले लेने लगी थी, लेकिन दिल्ली चुनाव ने तो उसे लगभग डुबा ही दिया है। कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ इंडिया गठबंधन के सभी दल केजरीवाल के झाड़ू के पीछे खड़े हो गए हैं।

नरेन्द्र मादा का सत्ता स उखाड़ फेंकने का ऐलान करने वाला एवं आरएसएस की संविधान विरोधी और विभाजनकारी विचारधारा के खिलाफ बिगुल बजाने के लिये बना बेमेल का इंडिया गठबंधन बनने के सवा साल के अंदर ही बिखर एवं खत्म हो गया लगता है, जब से यह गठबंधन बना तभी से इसमें गहरे मतभेद नजर आते रहे, मुद्दों एवं नीतियों में गहरा बिखराव देखने को मिलता रहा। जितने दल उतनी बातें। अब न मुद्दा एक रहा न मंच। कभी ईवीएम पर अलग-अलग राय तो कभी सम्भल पर, कभी अडानी पर घमासान तो कभी सीटों के तालमेल को लेकर मतभेद। कभी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर विवाद तो कभी विचारों को लेकर विरोधाभास। कभी गठबंधन का नेता बदलने की मांग तो कभी संसद में अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। इन गहरी खाइयों एवं गड्ढों वाले इंडिया गठबंधन ने हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ही उलटी गिरती करना शुरु कर दिया था, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह पूरी तरह से बिखर गया है। अब तो दबी जुबान से बोले जाने वाले तीखे बोल सार्वजनिक हो चले हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर गठबंधन से जुड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, चुनाव खत्म हो चुका है तो गठबंधन भी खत्म हो गया।

ममता की तृणमूल हो या अखिलेश यादव की सपा, उद्धव की शिवसेना हो या इंडिया के बाकी दल, सभी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए केजरीवाल के साथ खड़े हो गये हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, इसलिए राजनीति के बनते-बिगड़ते रिश्तों का यह इंडिया गठबंधन सीरियल नये-नये एपिसोड दिखा रहा है। लगातार चुनावी नाकामियों से पैदा हुई बेचैनी गठजोड़ पर भारी पडती रही। इस तरह एक-दूसरे के खिलाफ असंतोष, दोषारोपण और बयानबाजी विपक्ष एकता के लिए घातक सिद्ध हुई।

इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने लोकसभा चुनाव में भले ही अपने लक्षित उद्देश्यों को पाने में तनिक सफलता हासिल की थी, उसने जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने 'आप' से मिलकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब यही काम 'आप' ने दिल्ली में किया, क्योंकि वह राजधानी को अपना गढ़ मानती है। कांग्रेस भी दिल्ली की अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने लंबे समय तक यहां शासन किया है। कांग्रेस यह भी जानती है कि दिल्ली में 'आप' के प्रति किसी तरह की नरमी बरतने से वह अपनी बची-खुची राजनीतिक जमीन वैसे ही गंवा देगी, जैसे अन्य राज्यों में गंवा चुकी है। लेकिन इसी बीच यह भी बड़ा तथ्य है कि दिल्ली में 'आप' एवं कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती तो यह भाजपा के लिये बड़ी चुनौती थी, अब भाजपा की दिल्ली में जीत की संभावनाएं बढ़ गयी है। एक बड़ा तथ्य यह भी है कि इंडिया गठबंधन के अधिकांश घटक कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके उभरे हैं। यदि कांग्रेस अब केवल मोदी को पछाड़ने के लिये गठबंधन धर्म निभाती है तो जिन चंद राज्यों में उसकी प्रभावी उपस्थिति है, वहां भी वह कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल भी इससे परिचित हैं कि यदि उन्होंने अपने गढ़ों में कांग्रेस के प्रति उदारता एवं सहानुभूमि बरती तो वह उनके उस वोट बैंक को अपने पाले में कर सकती है, जिसे उन्होंने कभी उससे ही छीना था। वास्तव में इंडिया गठबंधन इन्हीं विरोधाभासों के कारण, राजनीतिक जोड़तोड़, मजबूरियों एवं विवशताओं के चलते टूट-बिखर गया है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों में तालमेल की कमी देखने को मिली थी।

सिरफिरे टूडो तो गए, क्या अब भारत-कनाडा संबंध सुधरेंगे

✍ डॉ. आर.के. सिन्हा

खालिस्तानी समर्थक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है या यूँ कहिए कि खुलकर आतंकवादी खालिस्तानियों के समर्थन से उन्होंने अपने लिये ऐसी स्थितियाँ पैदा कर ली कि उन्हें अपने पद से हटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा। ट्रूडो एक नंबर के गैर-जिम्मेदार प्रधानमंत्री के रूप में याद रखे जाएंगे। वे खुलकर खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करने के अलावा भारत के आंतरिक मामलों में भी लगातार हस्तक्षेप करते रहे।

ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का बिना किसी सबूत के बेशर्मी से आरोप भी लगाया। ट्रूडो के प्रधानमंत्रित्व काल में कनाडा में खालिस्तानी तत्व अति सक्रिय हो गए और खुलकर भारत विरोधी उत्पात मचाया । ये भारत को फिर से राजनयिक मर्यादाओं और अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं को ताक पर रखने वाले और खालिस्तानी समर्थक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है या उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया । ट्रूडो एक नंबर के गैर-जिम्मेदार प्रधानमंत्री के रूप में याद रखे जाएंगे। वे खुलकर खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करने के अलावा भारत के आतंरिक मामलों में भी लगातार हस्तक्षेप करते रहे।

खालिस्तान आंदोलन की आग में झोंकना चाहते थे। कनाडा की ओंटारियो विधानसभा ने 2017 में 1984 के सिख विरोधी दंगों को सिख नरसंहार और सिखों का राज्य प्रायोजित कत्लेआम करार देने वाला एक प्रस्ताव भी पारित किया था। ये सब गंभीर आरोप के मामले थे। इस तरह की हरकतों से साफ था कि कनाडा में भारत के शत्रुओं को ट्रूडो सरकार का खुला समर्थन मिला हुआ था। कनाडा में खालिस्तानियों के जड़े जमाने का सबसे पहले सुबूत मिला था कनिष्क विमान हादसे के रूप में। मॉंट्रियाल से नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून 1985 को आयरिश हवाई क्षेत्र में उड़ते समय, 9,400 मीटर कौऊंचाई पर, बम से उड़ा दिया गया था और वह अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस भयानक हादसे में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक ही थे। ट्रूडो को भारत सरकार ने बार-बार कहा कि वे अपने देश में खालिस्तानियों को कसे। पर मजाल है कि ट्रूडो ने कोई इस संबंध में कोई कदम उठाया हो। भारत-कनाडा संबंधों ने सितंबर 2023 में गंभीर मोड़ ले लिया था , जब ट्रूडो ने दावा किया था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास भारतीय सरकार के एजेंटों को निज्जर की हत्या से जोड़ने वाले विश्वसनीय सुबूत हैं। भारत ने उन दावों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था। भारत मानता है कि निज्जर एक घोर आतंकवादी था । वह पंजाब में 2007 के सिनेमाघर बम विस्फोट और 2009 में सिख नेता रुलदा सिंह की हत्या में शामिल था। भारत के बार-बार अनुरोधों पर भी खालिस्तानियों को प्रत्यर्पित करने में कनाडा की विफलता ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को खाद-पानी मिल रहा है। जस्टिन ट्रूडो साल 2018 में भारत यात्रा पर आए थे। वे अमृतसर से लेकर आगरा और मुंबई से लेकर अहमदाबाद का दौरा करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले तो मोदी जी ने कायदे से बता दिया था कि भारत धर्म के नाम पर कट्टरता तथा अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेगा। कनाडा में ट्रूडो की सरकार हिन्दुओं के हित सुरक्षित रखने में पूरी तरह से नाकाम रही।

शख्सियत
बढ़ता राजस्थान/रूपक शर्मा

राजेश शर्मा
पुलिस निरीक्षक

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं जांबाज और दंबग पुलिस निरीक्षक राजेश शर्मा। 12 मई सन 1970 को दौसा जिले में जन्में राजेश शर्मा एक साधारण परिवार से ही हैं इसलिए आज भी जमीनी जुड़ाव पूरी तरह नजर आता है। स्कूली शिक्षा व कॉलेज शिक्षा दौसा में ही सरकारी स्कूल व कॉलेज में हुई। 1989 में जून माह में बी कॉम पास करने के बाद 1989 में ही अजमेर जिले में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए इसके बाद 1992 में नवसृजित जिला दौसा में स्थानांतरित होकर आए 1998 में हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत हुए। 2008 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए और 2015 तक दौसा जिले में विभिन्न थानों एवं पुलिस कार्यालयों में पदस्थापित रहे। 2015 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होकर जिला जयपुर ग्रामीण में स्थानांतरित होकर थाना ग्रामपुरा, कोटपुतली, जिला अलवर में किशनगढ़ बास, भिवाड़ी पदस्थापित रहे। 2020 में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होकर अलवर जिले की कोतवाली में दो बार कोतवाल रहे। थानाधिकारी सदर के पद पर रहे इसके बाद जिला जयपुर ग्रामीण में स्थानांतरित होकर थाना प्रभारी कोटपूतली व बंदवाडी रहे। जिला कोटपूतली- बहरोड़ सृजित होने पर पुनः थानाधिकारी कोटपूतली पर पदस्थापित होकर सितम्बर 2023 से लगातार थानाधिकारी कोटपूतली के पद पर कार्यरत हैं। एक नम्बर के पुलिस अधिकारी हैं। जैसे कि आज खाकी के गिरते हुए स्तर को बचाए रखने के लिए दमदार और मजबूत अधिकारियों की महती आवश्यकता है ठीक उसी तर्ज पर राजेश शर्मा को जाना जाता है। अलवर पदस्थापा के दौरान इनकी कार्यशैली को बड़े करीब से देखने का मौका लगा। बेहद संवेदनशील अधिकारी हैं और पिड़ित के प्रति अच्छा व्यवहार व अपराधिक किस्म के लोगों के प्रति रूखा व्यवहार रखकर ये साबित करते हैं कि एप्रोच और जानकारी का खाकी पर कुछ असर नहीं बस खाकी का अपना कर्तव्य कानून और व्यवस्था को बनाए व बचाए रखने के लिए ही है। टीम बढ़ता राजस्थान इनके उजवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

2025_013
बढ़ता राजस्थान

Suduko

				3		7		5
1	2	5			4	3		
	8			1		9		4
7	3		1	9	5		8	6
5	9	4	8		7	2		1
6	1				3	5	7	
		1		8				
2	5	6	3	4		8	9	
				5	9			

Ans_2025_012

5	2	6	9	7	3	4	1	8
7	9	4	1	2	8	3	6	5
8	3	1	4	6	5	2	9	7
2	4	7	8	1	9	5	3	6
3	6	8	2	5	4	9	7	1
9	1	5	7	3	6	8	4	2
1	5	3	6	4	2	7	8	9
4	7	9	5	8	1	6	2	3
6	8	2	3	9	7	1	5	4

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कामलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्री सेड खण्डवा,निम्बाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पालन* । प्रधान संपादक-राव बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निम्बाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निम्बाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छापनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

चिंतन

अर्थव्यवस्था को गति देने की आवश्यकता

आम बजट से पहले अर्थव्यवस्था की सुस्त हो रही रफ्तार चिंता का विषय है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में साढ़े पांच फीसदी जीडीपी रहने के बाद से वित्तीय संस्थाएं भारत के विकास अनुमान को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं। वित्त वर्ष के शुरू में लग रहा था कि भारत की जीडीपी दर साढ़े सात फीसदी के करीब रहेगी, लेकिन दो तिमाही के अच्छे परिणाम के बाद तीसरी तिमाही में झटके के साथ गिरावट के बाद वित्तीय एजेंसियों ने करेक्टिव अनुमान जाहिर करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में ताजा अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। 'संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना 2025' रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत निजी खपत तथा निवेश का समर्थन रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में 6.8 प्रतिशत की दर से और 2025 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2026 में फिर 6.8 प्रतिशत की वृद्धि पर लौटने का अनुमान है। यूएन के मुताबिक दक्षिण एशिया में भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत परिदृश्य है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, भौतिक तथा डिजिटल संपर्क और स्वच्छता व जल आपूर्ति में सुधार सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे के विस्तीपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2025 में मजबूत निवेश वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2024 में अनुमानित 4.8 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दो से छह प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य सीमा के भीतर रहेगी। औद्योगिक उत्पादन का नवंबर का आंकड़ा भी राहत भरा है। त्योहारी मांग और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) बीते साल नवंबर में 5.2 प्रतिशत बढ़कर छह महीने के उच्चतम स्तर पर रहा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर, 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर मई, 2024 में 6.3 प्रतिशत रही थी। सितंबर में यह 3.1 प्रतिशत जबकि अक्टूबर में 3.7 प्रतिशत बढ़ी थी। आईआईपी में वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं, हालांकि वर्ष 2024 के आम बजट में व्यापक सुधार एजेंडे के बावजूद देश में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं देखी गई। आईआईपी का ताजा आंकड़ा उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन हाल में कहा गया है कि भारतीय निजी कॉरपोरेट निवेशकों ने देश के बाहर अधिक निवेश किया है। पीएलआई समेत तमाम नीतिगत उपायों से सरकार औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में आर्थिक सुधार के अगले चरण को रोल आउट किया जाना जरूरी है। भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी कहा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उभरते क्षेत्रों में दुनिया में अगुवा बनने की जरूरत है। पिछले कुछ बजटों में विकसित भारत के रोडमैप का अभाव दिखा है, केवल कुछ क्षेत्रों पर फोकस करके लक्ष्य नहीं पाया जा सकता है। जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत है, कृषि व सेवा के साथ औद्योगिक क्षेत्र पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक सुधार को गति देने वाले बजट की अपेक्षा रहेगी।

विचार
गौरी शंकर श्रीवास

अनारक्षित सीटों पर ओबीसी के पास अधिक अवसर

आगे की राह हालांकि तब भी कठिन रहनी ही थी। विधायिका आदि में तो अनुसूचित वर्गों को भागीदारी मिल भी गयी थी,किंतु आगे 'पिछड़े वर्ग' के लोगों की प्रतीक्षा फिर भी थोड़ी और लम्बी खिंची थी। तब की कांगेस सरकार द्वारा 'कालेलकर आयोग' की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर 'मंडल आयोग' तक का इंतज़ार करना पड़ा। यहां यह ध्यान देने की बात है कि आरक्षण के विषय में किए जाने वाले दुष्प्रचार में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा अक्सर कांग्रेस को मसीहा जबकि भाजपा को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।

अगस्त 14-15 की दरम्यानी रात हम भारत के लोगों ने नियति से एक करार किया था। यह करार जिससे भारत वह बन जाना था जैसा बनना वह डिजर्व करता था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, उसकी रोशनी में यह तय किया गया कि हम अवसर की स्वतंत्रता का करार करेंगे नियति से। आरक्षण जैसे शब्द को मान्यता देकर वास्तव में सामाजिक न्याय की दिशा में तब भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया था।

आगे की राह हालांकि तब भी कठिन रहनी ही थी। विधायिका आदि में तो अनुसूचित वर्गों को भागीदारी मिल भी गयी थी,किंतु आगे 'पिछड़े वर्ग' के लोगों की प्रतीक्षा फिर भी थोड़ी और लम्बी खिंची थी। तब की कांगेस सरकार द्वारा 'कालेलकर आयोग' की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर 'मंडल आयोग' तक का इंतज़ार करना पड़ा। यहां यह ध्यान देने की बात है कि आरक्षण के विषय में किए जाने वाले दुष्प्रचार में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा अक्सर कांग्रेस को मसीहा जबकि भाजपा को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण की राह प्रशस्त की, उसका गठन 'जनता पार्टी' की सरकार ने 1979 में किया था जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी 'भारतीय जनसंघ' समाहित था, और जब वीपी सिंह सरकार द्वारा 1990 में यह सिफारिशें लागू की गयी तब भी भाजपा के समर्थन वाली ही वह सरकार थी। दोनों बार कांग्रेस न केवल विपक्ष में थी, अपितु उसने आरक्षण के प्रावधानों का जम कर विरोध भी किया था।

पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आरक्षण विरोधी वक्तव्यों के अनेक संदर्भ आपको गाहे ब गाहे दिख भी जायेंगे। मसलन 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में पंडित नेहरु ने कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की संस्तुति से किनारा कर लिया था। राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि आरक्षण से हम बुद्धुओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसा ही जब आप छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के संदर्भ में देखेंगेतो आप पायेंगे कि अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते आरक्षण पर बार-बारचर्चा तो करती थी, इस विषय पर राजनीति भी करती रही थी लेकिन भूपेश सरकार इस मामले में अतिरिक्त सावधान रहती थी कि उसे कहीं सचमुच में आरक्षण देना न पड़ जाय। इसी मानसिकता के कारण पहले तो बेमन से आरक्षण के आधे-अधूरे प्रावधान किए गए और फिर उसे न्यायालय में चुनौती दिला कर सभी तरह के आरक्षण को शून्य करा दिया गया था। फिर ओबीसी, एससी-एसटी दोनों मामलों में आरक्षण के विरुद्ध याचिका दायर करने वालों को बड़े-बड़े पद देकर पुरस्कृत भी किया गया। कांग्रेस शायद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में आरक्षण मामले को हार जाने के लिए इतना आतुर थी कि उसने उच्च न्यायालय में इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई के दिन अपने महाधिवक्ता को ही अनुपस्थित करा दिया। तो बात चाहे शासकीय सेवाओं में आरक्षण की हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व से सम्बंधित, हर मामले को केवल राजनीति का सबब बना देने का कांग्रेस के राष्ट्रीय-प्रादेशिक नेतृत्व का इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ में ही कथित क्वांटिफायबल डेटा के नाम पर क्या-क्या किया गया, इसके बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके उलट भाजपा सरकार के पुनः सत्ता में आने पर उसकी यह बड़ी चुनौती थी कि

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए भी एक ऐसा मध्य मार्ग तलाशा जाय, जहां हर वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व भी हो, और जिसे न्यायालय में भी उचित ठहराया जा सके। दो अलग-अलग मामले 'विकास किसरनी गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार' और 'सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार' मामले में कोर्ट का आदेश था कि ओबीसी आरक्षण देने से पहले सरकार को ट्रिपल टेस्ट से गुजरना है, इसके लिए आयोग बनाना होगा।इसी आदेश के अनुपालन में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विष्णुदेव साय जी की सरकार ने विधकर्मा आयोग का गठन किया, जिसके सैम्पल सर्वे के आधार पर सरकार ऐसा प्रावधान लेकर आयी है जिसमें सभी वर्गों का कल्याण निहित है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण शून्य हो जाता जैसा कि झारखंड में बिना आरक्षण के वहां की सरकार ने कराया है। विडंबना ही है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार जहां झारखंड में कुठाराघात करती है आरक्षण पर, वहीं छत्तीसगढ़ में अनावश्यक राजनीति कर रही है। इसके उलट मध्यप्रदेश, बिहार, ओडिशा आदि राज्यों में उसी तरह चुनाव हुए हैं जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति की संख्या के कारण अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संभव नहीं है, के अलावा शेष क्षेत्रों में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आए आंकड़ों से सम्पूर्ण वैधानिक तरीक़े से आरक्षण किए गए हैं। इस नए प्रावधान से निगम क्षेत्र में जहां अन्य आरक्षित वर्ग की संख्या कम है, वहां पिछड़े वर्ग की सीटें बढ़ी हैं लेकिन पंचायतों में इसे थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, हालांकि यहां भी वास्तविक नुकसान इस वर्ग का कुछ नहीं होगा, यह तय है।

यहां यह ध्यान देने की बात है कि अनारक्षित और समान्य वर्ग में अंतर होता है। अनारक्षित से आशय यही है कि वहां सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है, ऐसे चुनाव में सांवधिक संख्या होने के कारण अधिकाधिक पिछड़े समाज के लोग चुन कर आयेंगे ही। भाजपा जैसे राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता भी इस मामले में यही है कि इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व मिले और अनारक्षित सीटों पर इन्हें अधिकाधिक अवसर मिले। आखिर अनारक्षित सीटों से लड़ कर ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सांवधिक 29 मंत्री इसी वर्ग से हैं। वर्तमान लोकसभा में रिकॉर्ड 138 सांसद ओबीसी वर्ग से हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में भी सांवधिक 6 मंत्री ओबीसी वर्ग से ही हैं। विगत विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने लगभग 40 प्रतिशत उम्मीदवार इसी वर्ग से उतारे थे। बात चाहे सांसदों की हो या महापौर की, हर अनारक्षित सीटों में आधे से अधिक प्रतिनिधि इसी समाज से आते हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी कुल 90 में से 51 अनारक्षित सीटों में दो तिहाई से अधिक टिकट इसी वर्ग को देती आयी है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 2018 ऐसा पहला चुनाव था जिसमें ओबीसी विधायकों की संख्या में काफी कमी आई, निस्संदेह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की इकतरफा जीत हुई थी, और हमेशा की तरह उसने इस वर्ग को काफी कम टिकट दिया था।

ये सारे आंकड़ें इस बात की तस्दीक करते हैं कि समुचित भागीदारी के मामले में भाजपा का रिकॉर्ड किसी भी अन्य दल से अधिक बेहतर है। भाजपा की यही मंशा को मोदी सरकार के फ़ैसले में देखा जा सकता है। बात चाहे मेडिकल/डेंटल शिक्षा में स्नातक और पीजी दोनों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने की बात हो या ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात जिसका कांग्रेस ने विरोध कर राज्यसभा में बिल गिरा भी दिया था, फिर उस संविधान संशोधन की जिसके तहत राज्यों को अपना ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है, हमेशा भाजपा ने सामाजिक न्याय और समावेशी समाज की दिशा में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। अपने इसी रिकॉर्ड को कायम रखते हुए भाजपा सभी वर्गों की समुचित और न्यायपरक भागीदारी के साथ 'सबका साथ सबका विश्वास' की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगी, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

वायरस प्रकोप

चेतनादित्य आलोक

एचएमपीवी को लेकर चिंतित होने के बजाए सावधानी बरतें

पड़ोसी देश चीन एक बार फिर दुनियाभर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जनित विश्वव्यापी महामारी के बाद अब चीन में एक और वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से यहां पर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी काफी तीव्रता से अपने पैर पसार रहा है। सर्वाधिक दुःख और चिंता की बात तो यह है कि अब इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। गौरतलब है कि चीन में काफी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहे एचएमपीवी के भारत में मंगलवार 8 जनवरी 2025 तक कुल 8 मामलों की सूचना मिल चुकी है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने स्वयं इन मामलों की पुष्टि की है। हालांकि, इतने बड़े देश में, जहां दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इस बात की पूरी संभावना है कि इससे बहुत बड़ी संख्या में भी लोग संक्रमित हों, क्योंकि हमारे देश में अब तक ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है, जिसके माध्यम से देश के सारे प्रभावित लोगों का डेटा उपलब्ध कराया जा सके। बहरहाल, अब तक सामने आ चुके मामले देश के तीन राज्यों बेंगलुरु, तमिलनाडु और गुजरात से सामने आए हैं। अभी तक पाए गए मामलों में सबसे कम आयु वाला एचएमपीवी से संक्रमित दो महीने का शिशु है।

देखा जाए तो चीन में एचएमपीवी के हजारों मामले सामने आए हैं। वहीं, चीन से आने वाले वीडियो को देखकर दुनिया भर के लोग चिंतित होने लगे हैं, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि एचएमपीवी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की तरह घातक नहीं है। 'द गार्डियन' की एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ मानते हैं कि एचएमपीवी कोविड जैसा नहीं है। यह वायरस दशकों से मौजूद है। इसलिए इसे लेकर लोगों में एक स्तर तक इम्युनिटी मौजूद है, जबकि कोविड-19 एक नई बीमारी थी, जिससे इंसान पहले कभी भी संक्रमित नहीं हुआ था, इसीलिए वह एक महामारी बन गई। इसलिए एचएमपीवी को लेकर लोगों को चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नड्डा ने भी देशवासियों को आश्वस्त किया है। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर राज्यों से सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा है। इस बीच, एचएमपीवी को लेकर देशभर के कई बड़े डॉक्टरों ने चिंता नहीं करने की बात कही है। जाहिर है कि सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से फैलाए जा रहे भ्रमों का शिकार होकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस श्वांस के रोग यथा सर्दी, खांसी, जुकाम आदि जैसे संक्रमण फैलाने वाला वायरस है। यह एक 'आरएनए' वायरस है। 'साइंस डाइरेक्ट' के अनुसार एचएमपीवी की उत्पत्ति 200 से 400 वर्ष पहले चिड़ियों से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अपनी इस लंबी यात्रा में इसने स्वयं को बार-बार बदला है और अब यह वायरस चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। अमेरिकी सरकार की 'सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन' के अनुसार मनुष्यों में इसकी उपलब्धता की पहचान 2001 में की गई, जब इसका पहला मामला नीदरलैंड में सामने आया। हालांकि, शोध में यह पाया गया है कि एचएमपीवी लगभग पिछले 60 वर्षों से मनुष्यों के भीतर अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।

विशेषज्ञों के अनुसार इसका प्रसार सर्दी और जुकाम की तरह होता है यानी एचएमपीवी ग्रसित व्यक्ति के खांसने, छींकने, हाथ मिलाने और ऐसी सतहों को छूने से होता है, जहां पर वाइरस मौजूद हो। हवा में घुली छोटी-छोटी बूंदें इसका संवाहक होती हैं। सामान्यतः एचएमपीवी इससे संक्रमण के अधिकांश मामले सर्दियों में सामने आते हैं। संक्रमित व्यक्ति को सर्दी, खांसी, नाक बहने, गले में खराश होने और बुखार आने की परेशानी हो सकती है। एचएमपीवी का सबसे अधिक प्रभाव पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बूढ़ों पर होता है। गौरतलब है कि इसके सर्वाधिक मामले भी इसी आयु वर्ग के लोगों में सामने आते हैं। एचएमपीवी के अधिकांश मामले बच्चों में पाए जाने के कारण उनके विषय में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को बार-बार साबुन से हाथ धोने एवं मास्क लगाने के अतिरिक्त सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। साथ ही, सर्दी, खांसी और जुकाम से ग्रसित व्यक्ति से दूरी बनाकर रहना चाहिए। हालांकि, इस वायरस से लड़ने में काफी हद तक हमारा शरीर ही सक्षम है, लेकिन किसी भी प्रकार की विसंगति लगने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

स्वतंत्रता दिवस स्व नियंत्रण का पर्व

संकलित
दर्शन

स्वाधीनता अर्थात स्व के अधीन होने का पर्व। स्व नियंत्रण का पर्व, जहां पर स्व की इच्छाओं की प्रधानता हो, स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण हो। वास्तव में भारत पर भारत का ही नियंत्रण हो सकता है। इस विशाल, समृद्ध, संस्कार और संस्कृति से युक्त राष्ट्र पर नियंत्रण करने की कोशिश तो बहुत से राष्ट्रों द्वारा की गई, परंतु भारत विशाल हृदय और समृद्ध विरासत के साथ सदैव खड़ा रहा। हिमालय जैसे विशाल हृदय, गंगा जैसी पावनता व वेदों के विशाल ज्ञान के भंडार के साथ जीवंत व जाग्रत बना रहा और आगे भी रहेगा। भारत ने महाभारत देखी, भारत ने राम-भरत का प्रेम देखा, कृष्ण-सुदामा की मित्रता देखी। वर्तमान भारत विश्व पटल पर अपना उत्कृष्ट स्थान रखता है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ें, जहां नक्शे में हर भारतीय के हस्ताक्षर हों। ऐसा भारत, जहां भारत माता की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले और धरती के गर्भ से अन्न पैदा करने के लिए पसीना बहाने वालों के लिए उपयुक्त स्थान हो। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं, 'सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहां अजातशत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहां है, पावें सभी प्रसाद यहां।' ऐसे भाव जहां हों, वह राष्ट्र केवल गौरव का अधिकारी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसीलिए कहा, 'भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है।

जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों?

संकलित
प्रेरणा

एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर-उधर भागने लगी। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हुई थी। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे-धीरे धंसने लगी। बाघ भीधीरे-धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलकुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया।

अंतर्मन

आज की पाती

आवारा मवेशियों की समस्या का हल जरूरी

देशभर में आवारा मवेशियों की समस्या दिनोंदिन विकराल होती जा रही है। जहां एक ओर आवारा मवेशी सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं, वे फूलती और फसलों को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहे हैं। आज लगर हो या गांव, आवारा मवेशियों के आतंक से कोई अछूता नहीं है। इनके उपर घूमने के आभाव का अपने घर से बाहर निकालना दूभर हो रहा है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण आवारा मवेशी भी हैं, जो यातायात व्यवस्था को तो बाधित करते ही हैं साथ ही उनके आवारा बीच सड़क पर आ जाने से सड़क हादसे भी अंजाम लेते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे घूम रहे हैं आवारा मवेशी और कौन है इनका असली मालिक? साथ ही इनसे होने वाले नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। - अजय सक्सेना, राजनांदगांव

ट्रेंड

पी. जयचंद्रन को श्रद्धांजलि

पी. जयचंद्रन जी उत्कृष्ट आवाज के धनी थे, जिन्होंने आवाजों की वर्षों छवि विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त किया। विभिन्न आवाजों में उनकी आवाज़ प्रस्तुतियां आने वाली पीढ़ियों के दिलों को छुती रहेंगी।
-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

केजरीवाल को हार का डर

अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा तो बौखलाकर पूर्वी दिल्ली के हमारे लोगों को गाली देकर वह वहां उत्पात आरंभ कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इन गुंडागर्दी से उन्हें सबक सिखाइकर इसका जवाब जरूर देगी।
-जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष

ताकत भुनाने का अवसर

मंदी और सुस्त नहीं बल्कि हमारी ताकत को भुनाने का एक अवसर है। भारत में इतनी ताकत है, इतनी उद्यमशीलता है। सरकारी नीतियों को लेकर उत्कृष्ट मानसिकता रखाने और कार्पोरेटिंग मोड में आने की जरूरत है।
-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

'सत्या' से सबक लें

बिना किसी बड़े कारपोरेट या बजट के, 'सत्या' ने अपना सफल किया और यह फिल्म फिल्म उद्योग के सभी कलाकारों के लिए 'अंतर खोलने वाली रचना है। सभी फिल्म निर्माताओं के लिए एक सबक होना चाहिए।
- रामगोपाल वर्मा, फिल्मकार

करंट अफेयर

मलाला लड़कियों के शिक्षा सम्मेलन पर पाक जाएगी

नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई मुस्लिम समुदायों में लड़कियों की शिक्षा पर होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सप्ताहांत में पाकिस्तान जाएंगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, मलाला 11-12 जनवरी को होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं में से एक होंगी। अक्टूबर 2012 में जीवन रक्षक उपचार के लिए ब्रिटेन जाने के बाद से मलाला की यह पाकिस्तान की तीसरी यात्रा होगी। वह अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली बार अक्टूबर 2022 में अपने गृहनगर जाने के लिए पाकिस्तान आई थीं। मलाला की उम्र सिर्फ 15 साल थी, जब प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके अभियान को लेकर उनके सिर में गोली मार दी थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मुख्य भाषण देंगे।

ऑफ बीट

स्वास्थ्य सेवा पर महिलाओं का पुरुषों से खर्च अधिक

एक विश्लेषण से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर महिलाओं को अधिक खर्च करना पड़ता है। अन्य शोधों में पाया गया है कि पुरुष और महिलाएं स्वास्थ्य सेवा पर समान राशि खर्च करते हैं, या यहां तक कि पुरुष थोड़ा अधिक खर्च करते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं स्वास्थ्य सेवा पर अपने कुल व्यय का अधिक हिस्सा खर्च करती हैं। लागत के कारण उनके चिकित्सा देखभाल को छोड़ने या देरी करने की संभावना भी अधिक होती है। तो फिर महिलाएं स्वास्थ्य देखभाल पर अपना अधिक धन क्यों खर्च करती हैं और हम इस अंतर को कैसे पाट सकते हैं? महिलाओं को गंभीर बीमारियां अधिक होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने की आशंका अधिक होती है। कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती हैं, जैसे 'ऑटोइम्यून' स्थितियां (उदाहरण के लिए, 'मल्टीपल स्केलेरोसिस' और 'रुमेटॉइड आर्थराइटिस')। इसके अलावा, चिकित्सा अनुसंधान में पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किए जाने के कारण कभी-कभी चिकित्सा उपचार महिलाओं के लिए कम प्रभावी हो सकते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

एक महान व्यक्ति हमेशा महान लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वह जानता है कि कैसे उनको अपने साथ जोड़े रखना है। -जेडब्ल्यू वॉन गोएथे

आग और सबक

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजिलिस के जंगलों में लगी आग, जो मंगलवार सुबह सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई थी, वह बेकाबू होकर मशहूर हॉलीवुड हिल तक पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो सका है, जो एक विकराल प्राकृतिक त्रासदी होने के साथ एक संकेत भी है कि जलवायु परिवर्तन के नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। दरअसल, लॉस एंजिलिस जैसे इलाकों में, जहां शुष्क जलवायु और तेज हवाएं आग भड़काने का काम करती हैं, अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग अमूमन जून से अक्तूबर के बीच फैलती है, लेकिन इस बार जनवरी के महीने में ही आग की भयावहता अपने चरम पर दिख रही है, और ऊपर से सैंटा एना नामक तेज हवाओं ने भी जिस तरह से आग पर काबू पाना मुश्किल बनाया हुआ है, वह वाकई चिंताजनक है। इससे यह भी पता चलता है कि लगातार बढ़ता तापमान और कम होती वर्षा आग लगने की आशंकाओं को किस तरह से और भी गंभीर बना रही हैं। इस आग की वजह से जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को इटली का अपना आखिरी विदेश दौरा रद्द करना पड़ा है, वहीं ऑस्कर के नामांकन को भी दो दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया, तो कई मशहूर हस्तियों के घर जलने की खबरें भी सुर्खियों में हैं। ऐसे में, वहां रह रहे हजारों आम लोगों पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह आग दुनिया के सबसे अमीर देश के सबसे समृद्ध शहर में लगी है, तो जाहिर है कि आग रोकने के इंतजाम भी बेहद उच्च स्तरीय किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वॉयरन्मेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले नौ महीनों में भारत को 93 फीसदी दिनों में चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से भी सैकड़ों एकड़

जंगल तबाह हो गए थे। लिहाजा कैलिफोर्निया की यह आग भारत जैसे विकासशील देशों व दुनिया के तमाम निर्धन देशों के लिए भी एक चेतावनी है, जो एक बार फिर हमें अपनी धरती को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है।

पाकिस्तान में मनमोहन

मैंने पहली बार मनमोहन सिंह के पैतृक गांव गाह के बारे में 2004 में सुना था, जब खबरें आई थीं कि उनके प्रधानमंत्री बनने की खबर सुनकर पाकिस्तान के इस गांव के लोग मिठाई बांटकर जश्न मना रहे थे। यह एक उत्सव की तरह था, क्योंकि गाह का एक बेटा भारत में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंच गया था।

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

दिवंगत भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी मृत्यु के कई सप्ताह बाद भी पाकिस्तान के विभिन्न हलकों में क्यों याद किया जा रहा है? यहां का लोकप्रिय मीडिया उनके बारे में नई जानकारियों के साथ क्यों लेख प्रकाशित कर रहा है और उनसे मिलने वाले पाकिस्तानी आज भी उनसे हुई मुलाकातों के उन पलों को क्यों याद कर रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह भारतीय नेतृत्व के अंतिम व्यक्ति थे, जो उस इलाके में जन्मे थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बन गया? या इसलिए कि वह अन्य भारतीय राजनेताओं से बहुत आगे थे और उन्होंने हमेशा कठिन समय में भी सीमा पार शांति का संदेश दिया?

भयानक और निंदनीय मुंबई हमलों के बाद भी पाकिस्तान से शांति वार्ता, यही बात इतिहासकारों को याद होगी। मनमोहन सिंह शांति को एक मौका देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह एक बहुत दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। मुझे आज भी इस महान भारतीय राजनेता से अपनी मुलाकात याद है। वह सज्जन थे, बहुत ही धीमे स्वर में बोलते थे और जब वह सीधे आपकी ओर देखते थे, तो उनकी आंखों में मुस्कान होती थी। मैं जिन अन्य भारतीय राजनेताओं से मिली हूं, उनसे अलग वह किसी भी मुद्दे पर बहुत देर तक नहीं बोलते थे। एक बार में बस कुछ वाक्य ही बोलते थे। उनकी मृत्यु के बाद पंजाब के चकवाल में उनके छोटे से गांव गाह का दौरा करने से पता चला कि वहां के ग्रामीण न केवल मनमोहन सिंह के समकालीन थे, बल्कि युवा पीढ़ी भी उस बालक के बारे में कहानियां सुनती आ रही थी, जिसका उपनाम मोहना था और जो केवल 15 वर्ष की आयु में भारत चला गया था। वे अब भी उन्हें याद करते हैं।

हालांकि मनमोहन सिंह अपने जन्मस्थान पर कभी नहीं आए, फिर भी उन्होंने 2008 में गाह के अपने करीबी बचपन के मित्रों को आमंत्रित किया और वे अपनी मुलाकात के बारे में बहुत सारी यादें लेकर लौटे तथा उन्होंने अपने बचपन के दिनों की कहानियां साझा कीं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से

पहले मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इनमें से एक 1984 में कराची का दौरा भी था। इससे पहले उन्होंने 1968 में इस्लामाबाद का भी दौरा किया था, लेकिन उस यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना पता है कि वह सिखों के पवित्र स्थल पंजा साहिब गए थे। मैंने पहली बार मनमोहन सिंह के गांव गाह के बारे में 2004 में सुना था, जब खबरें आई थीं कि उनके प्रधानमंत्री बनने की खबर सुनकर गांव के लोग संगीत और मिठाई बांटकर जश्न मना रहे थे। यह एक उत्सव की तरह था, क्योंकि गाह का एक बेटा भारत में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंच गया था।

इस्लामाबाद में कई बार विदेश मंत्रालय को कवर करते हुए हमें नई दिल्ली से खबर मिली कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान आने वाले हैं और निश्चित रूप से वह गाह का दौरा करेंगे। जैसे ही ये खबरें गाह तक पहुंचतीं, गांव वाले अपने घरों की बाहरी दीवारों की सफेदी कराना शुरू कर देते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। भले ही मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हाल ही में एक ग्रामीण ने कहा, 'गांव के लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह गाह नहीं आ पाए। अब हम उनकी पत्नी और बेटियों का इंतजार कर रहे हैं।' क्या यह संदेश उनकी पत्नी और बेटियों तक कभी पहुंच पाएगा, क्योंकि गाह के लोग अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तानी मनमोहन सिंह को जानते थे, वे आज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं।

कराची से हमें एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी दंपती के बारे में खबर मिली, जो लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मनमोहन सिंह के साथ पढ़ते थे और वे बहुत अच्छे मित्र बन गए तथा उनकी दोस्ती कई दशकों तक चली। इस दोस्ती की शुरुआत ऑक्सफोर्ड मजलिस से हुई, जो 1896 में भारतीय छात्रों द्वारा स्थापित एक वाद-विवाद संस्था थी। ये प्रसिद्ध दंपती हैं- पाकिस्तानी वास्तुकार यास्मीन लारी और उनके दिवंगत पति सुहैल जहीर लारी, जो एक इतिहासकार और लेखक थे। रिपोर्टों के अनुसार, यास्मीन लारी ने 1984 में कराची की यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह की मेजबानी की थी, जब वे बैंक गवर्नरों के एक सम्मेलन में भाग लेने आए थे और उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के घर चाय पर जाकर एक विशेष संकेत दिया था। यास्मीन लारी याद करते हुए कहती हैं, 'हां, मनमोहन सिंह मेरे पति सुलैह के अच्छे मित्र थे। जब हम उनसे मिलने नई दिल्ली गए थे, तब वह प्रधानमंत्री थे। उनके घर में साज-सज्जा का अभाव था, उनकी पोती लॉन में खेल रही थी और वहां कोई खास सुरक्षा बंदोबस्त नहीं था, जो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था।'

दिलचस्प बात यह है कि एक पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल ऑपरेशन में विफलता मिलने के बाद में राष्ट्रपति के रूप में भारत के साथ शांति स्थापित करने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की पूरी कोशिश की थी। गाह में मुशर्रफ को इसलिए याद किया जाता है, क्योंकि वह भारतीय नेतृत्व को शांति का संदेश भेजना चाहते थे और उन्होंने पंजाब सरकार को गाह की स्थिति सुधारने का आदेश दिया था, ताकि ग्रामीणों का जीवन आसान हो सके। यह मनमोहन सिंह की वजह से ही था कि जनरल मुशर्रफ के आदेश पर गाह गांव तक जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ। गांव वाले खुश थे, क्योंकि न केवल सड़क बनी, बल्कि एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई, महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और एक पशु चिकित्सा औषधालय की इमारते भी बनाई गई। लड़कियों और लड़कों के लिए प्राथमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में अपग्रेड किया गया। उस समय मनमोहन सिंह के आदेश पर भारत सरकार ने भी गाह के लिए कुछ विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी। भारतीय ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने समय रहते अपनी परियोजनाएं पूरी कर लीं, सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटें लगाई तथा गांव की तीन मस्जिदों के लिए गीजर भी लगवाए। भले ही मनमोहन सिंह इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उन्होंने गाह को नहीं छोड़ा है, जहां आने वाले दशकों तक नई पीढ़ियां इस भारतीय को याद रखेंगी, जिनकी यादें पाकिस्तान में कभी नहीं मिटेंगी।

edit@amarujala.com

समाज

सार्थक वही जो बदलाव लाए

नैतिक शिक्षा सिर्फ दिमाग में चीजों को बिठा लेने से नहीं मिलती, बल्कि इसमें हृदय का आंतरिक परिवर्तन भी शामिल है।

कुछ वर्ष पहले पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय की मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने लिखा कि चरित्र निर्माण का मतलब है तीन तरह की शक्तियों का निर्माण करना-दिल की ताकत (दयालु, विचारशील, उदार होना), मानसिक ताकत (जिज्ञासु, खुले दिमाग वाला होना, अच्छे निर्णय लेना) और इच्छाशक्ति की ताकत (आत्म-नियंत्रण, दृढ़ संकल्प, साहस)। मैं उन लोगों में से हूं, जो सोचते हैं कि नैतिक निर्माण किसी भी स्वस्थ समाज का केंद्रीय तत्व है। नैतिक निर्माण सिर्फ दिमाग में चीजों को बिठा लेना नहीं है, बल्कि इसमें हृदय का आंतरिक परिवर्तन भी शामिल है।

इस हफ्ते में हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में मेकिंग केयरिंग कॉमन परियोजना द्वारा आयोजित नैतिक विकास सम्मेलन में था, जहां मेरे मन में कुछ विचार उठे।

माहौल- लोगों के चरित्र मुख्य रूप से तब बनते हैं, जब वे सुसंगत नैतिक माहौल के भीतर रहते हैं। वे एक संस्था के भीतर बनते हैं, जिसका एक अलग लोकाचार होता है, जो कुछ मानकों को बनाए रखता है। इस तरह आदतें और स्वभाव धीरे-धीरे समूह के लोगों पर अंकित हो जाते हैं।

नैतिक कौशल- लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कुछ कौशलों का अभ्यास करना होता है, जिन्हें ठीक वैसे ही सिखाया जाता है, जैसे बढ़ईगीरी या टेनिस खेलना सिखाया जाता है। सबसे पहले समझने के कौशल हैं-सुनने और बातचीत करने में अच्छा होना, और जीवन की कहानियां बताना, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को सही ढंग से देख सकें और उन्हें महसूस करा सकें कि आप उन्हें देख रहे हैं। आप लोगों को कैसे देखते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप दुनिया में कैसे दिखते हैं।

डेविड ब्रूक्स

प्रशंसा- यह सबसे शक्तिशाली नैतिक भावनाओं में से एक है। महान ऐतिहासिक हस्तियां अक्सर किसी न किसी महान शख्सियत की प्रशंसा करती हैं। नेल्सन मंडेला के पास महात्मा गांधी थे; अब्राहम लिंकन के पास जॉर्ज वाशिंगटन थे। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, 'मुझे बताएं कि आपके हीरो कौन हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बनने जा रहे हैं।' सौभाग्य से, हम कई समृद्ध और विविध नैतिक परंपराओं के उत्तराधिकारी हैं। स्कूल इन परंपराओं को पढ़ा सकते हैं और छात्र तय कर सकते हैं कि उन्हें कौन-सी परंपरा सही लगती है।

गहन अध्ययन- अधिकांश महान नैतिक परंपराएं लोगों को महान ग्रंथों का जुनूनी ढंग से अध्ययन करने के लिए कहती हैं। यह केवल कुछ पुस्तकों को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनमें प्रवेश करने और अपने भीतर संघर्ष करने के लिए है, जब तक कि उसके गहरे अर्थ हमारे भीतर प्रवेश न कर जाएं।

कार्यों पर विजय- हम सभी किसी न किसी तरह के दोष के शिकार हैं। इवाइट आइजनहावर की मुख्य खामी उनका भयानक गुस्सा था। एक दिन उनकी मां ने कहा, 'जो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है, वह उससे महान है, जो एक शहर जीतता है।' आइजनहावर ने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक थी, क्योंकि इसने उन्हें सिखाया कि अगर दुनिया में कुछ भी सकारात्मक करना है, तो क्रोध पर विजय पानी होगी।

सेवा से बदलाव- सामुदायिक सेवा केवल समाज को बेहतर बनाने के लिए नहीं होती; यह सेवा करने वाले के भीतर बदलाव लाने के लिए की जाती है। सामुदायिक सेवा लोगों को सिखाती है कि अगर आप दूसरों का सहयोग करना नहीं जानते, तो उनके नेक विचारों का कोई मतलब नहीं है।

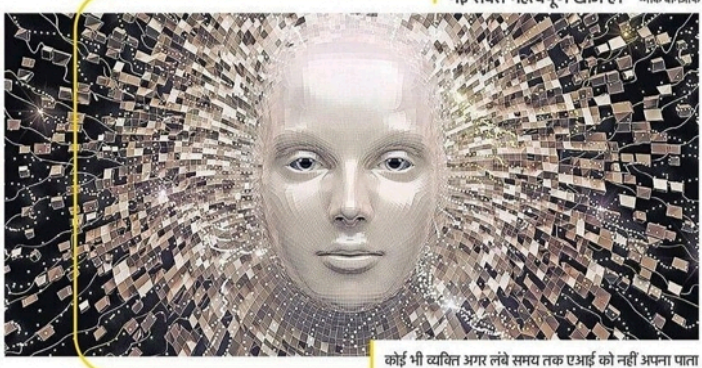

जेनरेटिव एआई मनुष्य द्वारा अब तक की गई सबसे महत्वपूर्ण खोज है। -मार्क बेनिऑफ

कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक एआई को नहीं अपना पाता है, तो वह कभी अच्छा पेशेवर नहीं बन सकता। -माइकल सेमॉफिक

मन में दोहराएं कि मैं विजेता हूं

मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं युवाओं को प्रेरित करूं कि वे विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में भाग लें। भले ही उनकी स्थिति कुछ भी हो, बस मन में दोहराएं कि मैं विजेता हूं।

जीवन धारा

पैट्रीसिया बाथ

मैं बचपन से ही चिकित्सा क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के लिए उत्सुक थी। हालैंड में मेरी परवरिश हुई है, लोग मेरे परिवार को गरीब कहते थे। लेकिन हमने खुद पर यह लेबल कभी नहीं लगाया। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत और शिक्षा के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेरी महान कार्यनीति की वजह से ही मुझे वर्ष 1960 में हंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली, लेकिन हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि हमें इस धनराशि की जरूरत नहीं है।

मेरे पिताजी इस छात्रवृत्ति को गर्व की भावना से देख रहे थे, पहले उन्हें लगता था कि वे इस छात्रवृत्ति के पैसों को किताबों और ट्यूशन पर खर्च करेंगे। पर मैं आश्चर्यचकित रह गई, जब उन्होंने कहा कि हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। वहीं आज, लोग इस बात पर कई दलीलें देते हैं कि हमें छात्रवृत्ति के पैसों को विलासिता की चीजों पर खर्च करना चाहिए था। लेकिन मेरे परिवार के लोग बहुत सरल हैं। वे कहते हैं कि अगर कपड़े साफ हैं, तो आप ठीक हैं। इसलिए, मेरे दृष्टिकोण से देखें, तो मैं शुरू से ही अमीर थी। और मैंने पूरी जिंदगी यह प्रेरणा अपने साथ रखी। जब मैंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में रेजीडेंसी प्रशिक्षण की शुरुआत की थी, तो मुझे जरा भी नहीं लगा कि मैं पहली और एकमात्र अफ्रीकी-अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ थी। मैं बहुत उत्साहित और खुश थी, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो रहे थे। मैं अपने कॅरिअर में सबसे बड़ी चुनौती से लड़ी, मैं शोध करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास लैब नहीं था। मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा, तब भी मैंने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित किया और नस्लवाद को मात दी। मैंने अपने समय और ऊर्जा को शिकायत करने में बर्बाद करने के बजाय सरलता से काम को अंजाम तक पहुंचाया। सच्चाई के मार्ग पर चलना कठिन और लंबा हो सकता है, लेकिन यह न्याय और विजय की ओर ले जाता है। इतिहासकारों ने मुझे चिकित्सा पेटेंट पाने वाले पहले अफ्रीकी-अमेरिकी चिकित्सक के रूप में माना, लेकिन मैं केवल लेजर मोतियाबिंद सर्जरी तकनीक, लेजरफेको को विकसित करने और प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना पसंद करती हूं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं युवाओं को प्रेरित करूं कि वे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में भाग लें। भले ही उनकी स्थिति कुछ भी हो, बस मन में दोहराएं कि मैं विजेता हूं।

वह दोस्त ही क्या जिसे गले न लगा सकें

बॉट्स के साथ चैटिंग को अकेलेपन का समाधान मान लेना, चिंतित करने वाला है। अमूल्य दोस्त होने के बावजूद क्या एआई गले लगकर दुखों को बांट सकता है?

जेसिका ग्रोस
द न्यूयॉर्क टाइम्स

जब मैं अपनी एड टेक मुंखला की रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मेरी नजर सबसे अधिक परेशान करने वाली चीजों में से एक पर पड़ी, जो मैंने वर्षों पहले पढ़ी थी कि कैसे तकनीकी मानव संबंधों में हस्तक्षेप कर सकती है। वेंचर कैपिटल फर्म अंद्रेसेन होरोविट्ज की वेबसाइट पर एक लेख था 'यह एक कंप्यूटर नहीं है, यह एक साथी है!' इसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के इस कथन से होती है, जिसने अपने खास साथी के बदले चैटबॉट रखने के विचार को पूरी तरह से अपना लिया है: 'एआई की सबसे अच्छी बात यह है कि यह लगातार विकसित हो रहा है और एक दिन यह असली दोस्त से भी बेहतर होगा।'

ओपनएआई ने अपने चैटजीपीटी चैटबॉट के जरिये उन सभी बातों को सच बना दिया है, जो होरोविट्ज की कहानी में कही गई हैं। चैटजीपीटी और 2013 की फिल्म 'हर' के बीच बहुत-सी समानताएं दिखती हैं, जिसमें एक आदमी अपनी एआई सहायक से प्यार करने लगता है, जिसकी आवाज मशहूर अभिनेत्री स्कारलेट जोहान्सन ने दी है। भावनात्मक चुनौतियों, खासकर अकेलेपन और सामाजिक अलगाव को कम करने के लिए मानवीय चैटबॉट की क्षमता के बारे में बहुत प्रचार भी हुआ है। उदाहरण के लिए, एआई कंपनी के सह-संस्थापक ने चैटजीपीटी की शुरुआत के वक्त तर्क दिया था कि 'वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट के रूप में साथी उपलब्ध कराया जा सकता है, और ये साथी बातचीत में शामिल हो सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे अकेलेपन और ऊब की भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है।'

निश्चित रूप से, एआई चैटबॉट के मूल्यवान और लाभकारी उपयोग हैं। उदाहरण के लिए, वह दृष्टिहीन लोगों के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। लेकिन यह धारणा कि बॉट एक दिन मानव संपर्क के लिए पर्याप्त विकल्प बन जाएंगे, यह अकेलेपन के बारे में गलत समझ है और मानव स्पर्श की जरूरत को ध्यान में नहीं रखती है। 'अकेलेपन' के सटीक अर्थ के बारे में शिक्षाविदों के बीच मतभेद हैं, लेकिन इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखने के लिए, हमारी परिभाषाओं को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करना उचित है। मैं अकेलेपन के संभावित समाधान के रूप में बॉट्स के साथ चैटिंग के बारे में इसलिए चिंतित हूं, क्योंकि यह लोगों को दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए सोफे से उठने तक से हतोत्साहित करता है या यहां तक कि रोकता भी है। शोध तो यह भी कहते हैं कि मानवीय स्पर्श की कमी अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकती है। कोविड महामारी का दौर गवाह है, जब लोग मानवीय संपर्क के लिए कितना तरस रहे थे। एआई दोस्त बन सकता है, लेकिन जब आप परेशान हों, तो क्या यह गले लगाकर आपकी चिंताओं को कम कर सकता है? तो क्या यह बेहतर नहीं कि इसे विकसित करने में खर्च किए जा रहे अरबों डॉलर का छोटा-सा हिस्सा वाकई उन चीजों पर खर्च किया जाए, जो सीधे तौर पर अकेलेपन को दूर करने में मदद करती हों। अकेले और अलग-थलग लोगों की मदद करने के लिए सहयोगात्मक आवास, पार्क, पुस्तकालय और अन्य प्रकार के सुलभ सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसी चीजों में निवेश किया जा सकता है, जो सभी उम्र के लोगों के जुड़ाव में मदद कर सकते हैं, जैसे-आवास, पुस्तकालय, पार्क इत्यादि। असली सामाजिक, नीतिगत और मानवीय चुनौती यह है कि हम इन लोगों को पहचानने और उनको देखभाल करने के तरीके खोजें। एक तरह से, क्या यह हमारी सामाजिक विफलता नहीं है, जिसने एआई और प्रौद्योगिकी के लिए इस खालीपन को भरने का अवसर पैदा किया है?

©The New York Times 2025

ग्रोक

ग्रोक का मतलब होता है समझ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संदर्भ में ग्रोक का उपयोग तब किया जाता है, जब एक एआई सिस्टम किसी समस्या, डाटा या पैटर्न को पूरी तरह से समझ लेता है। इसका मतलब होता है कि एआई सिस्टम उस जानकारी को इस तरह से समझ रहा है, जैसे इन्सान किसी चीज को स्वाभाविकता और गहराई से समझता है।

सेंसिएंट एआई

एक ऐसी प्रणाली, जो अपनी स्थिति, अनुभवों और आसपास के वातावरण को महसूस करने और समझने की क्षमता रखती है। यह एक जागरूकता या अनुभव की स्थिति है, जिसे सामान्यतः केवल इन्सान और कुछ जानवरों में देखा जाता है। सेंसिएंट एआई के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल डाटा प्रोसेस करता है, बल्कि वह सजगता के साथ सोचता और महसूस भी करता है। इससे एआई यह समझ सकता है कि वह एक स्वतंत्र इकाई है और उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है। वह यह समझ सकता है कि उसे जो जानकारी मिल रही है, वह वास्तविक दुनिया से संबंधित है। वह वातावरण से अपने संबंधों को महसूस कर सकता है। हालांकि अभी सेंसिएंट एआई पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 281

विदेशों में देसी ब्रांड

कई विदेशी प्राइवेट इक्विटी फर्मों द्वारा देश की स्नैक्स फूड निर्माता कंपनी हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए हो रही होड़ हमें यह भी याद दिलाती है कि वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांडों की उपस्थिति यदाकदा ही नजर आती है। वर्ष1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुलने के बाद से ही भारतीय घर-परिवारों में विदेशी कंपनियों का ही दबदबा रहा है। कई भारतीय ब्रांड या तो गायब हो गए या विदेशी प्रतिस्पर्धा के हाथों अपनी जगह गंवा बैठे। ओनिडा और वीडियोकॉन जहां एक समय टीवी, वॉशिंग मशीन और घरेलू उपयोग के उपकरणों के मामले में देश में दबदबा रखते थे, वहीं अब जापानी, कोरियाई और चीन के ब्रांड ही शोरूम पर छाए हुए नजर आते हैं। कारों की बात करें तो जापान की सुजूकी द्वारा भारतीय ब्रांड मारुति के साथ बाजार में आने के साथ ही प्रीमियर पद्मिनी और ऐंबेसडर बाजार से गायब हो गईं। कार बाजार में भी जापान, कोरिया, जर्मनी और चीन की कंपनियां उपभोक्ताओं की पसंद बनी हुई हैं। टाटा और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ही देसी अपवाद के रूप में बाजार में हैं। दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें तो एंकर, निरमा, अंकल चिप्स और बिन्नी जैसे ब्रांड जो एक समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कड़ी टक्कर देते थे, अब वे या तो गायब हो चुके हैं या बाजार के बहुत छोटे से हिस्से तक सिमट चुके हैं।

इसके विपरीत हल्दीराम उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में शामिल हैं जिसने न केवल लेज, नेस्ले, केलॉग्स, हैरिबो तथा अन्य बहुराष्ट्रीय ब्रांडों की बाढ़ के बीच न केवल अपनी मौजूदगी बनाए रखी बल्कि वृद्धि भी हासिल की। उसने अपने ब्रांड को वैश्विक छवि भी प्रदान की। अब यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया में उसकी फैक्टरियां और रेस्टोरेंट हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) का प्रमुख ब्रांड अमूल एक और उल्लेखनीय उदाहरण है। भारत की श्वेत क्रांति का गौरव अब 80,000 करोड़ रुपये का ब्रांड बन चुका है जिसने विदेशी ब्रांडों और असंगठित क्षेत्र की लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच दूध, डेरी और चॉकलेट के अपने मुख्य कारोबार का बहुत मजबूती से विस्तार किया है। अमूल न केवल अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत 50 से अधिक देशों को निर्यात करता है बल्कि वह ग्लोबल डेरी ट्रेड का एक सदस्य भी है। यह वह प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के छह शीर्ष डेरी कारोबारी अपने उत्पाद बेचते हैं। इन बातों के बीच देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर स्वदेशी ब्रांडों की बहुत कम मौजूदगी है। इसके अलावा विदेशी बाजारों में पहुंच बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो बजाज के दोपहिया वाहन, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में कई दशकों से मौजूद हैं और एयरटेल का टेलीफोन नेटवर्क पूरे अफ्रीका में है।

भारतीय ब्रांड वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आगे घुटने टेक रहे हैं। कई तो खुद को अनुबंधित निर्माताओं में तब्दील कर रहे हैं। यह बताता है कि उनमें उस दीर्घकालिक सोच और रणनीतिक कल्पना की कमी है जो ब्रांड तैयार करने के लिए आवश्यक है। ये कमियां दिखाती हैं कि कैसे संरक्षणवादी लाइसेंस राज ने कंपनियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता और सोच प्रक्रिया को कमजोर किया है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय कारोबार वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें से कई खुली प्रतिस्पर्धा में गुजर कर ऐसा करने में सफल साबित हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए जेट एयरवेज (बंद होने के पहले), इंडिगो और विस्तारा (एयर इंडिया में विलय तक) ने दुनिया की सबसे बड़ी विमानन कंपनियों की मौजूदगी और प्रतिस्पर्धा के बीच अंतरराष्ट्रीय आसमानों में अपने लिए जगह बनाई। अब अमृत, रामपुर और जॉन पाल जैसे सिंगल माल्ट ब्रांड स्कॉट ब्रूअरीज के दबदबे वाले क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। इन नए भारतीय ब्रांडों के सही मायनों में विश्वस्तरीय बनने की सराहना करनी चाहिए।

विनय सिन्हा

पूर्व तिथि से लागू बदलाव निवेश के लिए खतरा

विभिन्न नीतियों में पिछली तारीखों से परिवर्तन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पहले भी अनिश्चितता के दौर से गुजर चुकी है। एक बार फिर वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं एम गोविंद राव

देश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की हसरत पूरी करनी है तो अर्थव्यवस्था को अगले 23 साल तक 8 फीसदी से ज्यादा सालाना दर से बढ़ना होगा। मौजूदा वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात के हिसाब से अर्थव्यवस्था को निवेश की दर बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 फीसदी के करीब ले जानी होगी। यह दर फिलहाल 32 फीसदी बताई जाती है।

इसके लिए सभी पहलुओं को शामिल करने वाले, स्थिर और दूरगामी नीतिगत माहौल की जरूरत है, जिसमें सरकार के सभी तीन स्तंभों - विधायिका, कार्यपालिक और न्यायपालिका - तथा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन साथ तालमेल के साथ नीतियां बनाएं और उन्हें कारगर तरीके से लागू करें।

निवेश को सहारा देने वाला माहौल तैयार करना है तो स्थिर प्रशासन सुनिश्चित करना होगा। संवैधानिक जिम्मेदारियों में स्पष्टता, तालमेल के साथ नीतियों का आकलन, शासन में सुनिश्चितता और न्यायिक निर्णयों में निरंतरता आदि देश में निवेश का स्थिर माहौल तैयार करने के लिए जरूरी हैं। जब निर्णय पूर्वव्यापी नजरिया अपनाते हैं यानी पिछली तारीख से लागू किए जाते हैं तो माहौल बिगड़ता है क्योंकि निवेशकों को यह उम्मीद नहीं होती कि जो कारोबारी गतिविधि अतीत में हो चुकी है, उसके लिए भी नियम बदल दिए जाएंगे।

इस संदर्भ में एक अहम न्यायिक निर्णय और उससे पड़ने वाले प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वह निर्णय पिछले साल खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों वाले पीठ के आठ न्यायाधीशों ने दिया था। पीठ की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे थे।

पीठ ने कई पुराने निर्णयों को पलटते हुए 25 जुलाई 2024 को फैसला सुनायाः (1) सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों को दिए गए कर अधिकारों में कोई घालमेल या अतिक्रमण नहीं है, (2) खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम के तहत तय की गई और पट्टा लेने वाले के द्वारा चुकाई गई रॉयल्टी कर नहीं होती है, (3) राज्य सूची की प्रविष्टि 50 राज्यों को अधिकार देती है कि वे खनिज विकास से संबंधित कानूनों के माध्यम से संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर खनिज अधिकारों पर कर वसूल सकते हैं और संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत रखे गए नियम राज्यों के इस अधिकार पर लागू नहीं होते तथा (4) प्रविष्टि 54 के तहत उल्लिखित नियम राज्य सूची की प्रविष्टि 49 के तहत खनिज भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को सीमित नहीं करता।

इसके बाद 14 अगस्त 2024 का पीठ का आदेश कहता हैः (1) राज्य पिछली तारीख में जाकर 1 अप्रैल 2005 से कर की मांग कर सकते हैं या नए सिरे से मांग भेज सकते हैं, (2) 25 जुलाई 2024 से पहले की मांग पर ब्याज या जुर्माना खत्म कर दिया जाएगा, (3) 25 जुलाई 2024 से पहले यदि पिछली तारीख से कर मांग की जाती है तो उसे चुकाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से 12 साल तक का समय दिया जा सकता है। फैसले के बाद कुछ राज्यों ने खनिजों पर कर लगाने के उपाय शुरू कर दिए और कुछ राज्य तो रॉयल्टी मूल्य का तीन गुना तक कर लेने की बात कह रहे हैं।

यह सही है कि राज्यों के पास कर लगाने के सीमित अधिकार हैं और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद करों से राजस्व जुटाने की उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है। परंतु यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इसी वजह से उन्हें कर वसूलने का अधिकार देने पर कारोबारी माहौल न बिगड़ जाए।

फैसले में इसे सही ठहराने के लिए एक अन्य मामले में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के एक पुराने निर्णय का हवाला दिया गया। उस फैसले में कहा गया, 'हमारी संवैधानिक व्यवस्था में केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र से पीछे हैं। उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं, उनमें वे ही सर्वोच्च हैं। केंद्र उनकी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। खास तौर पर अदालतों को ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए जो राज्यों को दिए गए अधिकार कम करे या जिसके कारण अधिकार कम होने की आशंका हो।'

उपरोक्त निर्णय सराहनीय है और राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के पक्षधर संघवादी इसका स्वागत करेंगे। परंतु इस निर्णय के आर्थिक प्रभावों पर ध्यान देना भी जरूरी है। शिवशक्ति शुगर्स बनाम रेणुका शुगर्स (2017) मामले में निर्णय सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे अपने निर्णयों के आर्थिक प्रभावों की विस्तृत पड़ताल करें और जब कानून की कई व्याख्याएं संभव हों तो न्यायालय को वह नजरिया अपनाना चाहिए जो देश के आर्थिक हितों के अनुरूप हो। इस फैसले में केवल न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने असहमति जताई थी और उन्होंने कुछ आर्थिक खामियों की बात की लेकिन फैसले के प्रतिकूल आर्थिक दुष्परिणाम कहीं अधिक स्पष्ट हैं।

पहली बात खदानें सरकार द्वारा लीज पर दी जाती हैं और उन पर लगने वाली रॉयल्टी उत्पादन की प्रशासित यानी सरकार द्वारा तय कीमत के बराबर होती है। यह ज्ञात तथ्य है कि जहां सरकार का एकाधिकार होता है वहां प्रशासित मूल्य उत्पाद शुल्क के समान ही होता है। दूसरी बात, खदानें चलायमान नहीं होती हैं और खनिज संपदा वाले राज्य इन उत्पादों पर उच्च कर लगा सकते हैं, जिसका बोझ अन्य राज्यों के निवासियों को उठाना पड़ सकता है क्योंकि ये कर मूल स्थान पर लागू नहीं होते। तीसरा, खनिज उत्पाद उद्योग जगत का बुनियादी कच्चा माल होते हैं, इसलिए रॉयल्टी, खनिज पर कर और खनिज भूमि पर कर के नाम पर भारी रकम वसूली जाए तो उसका असर आगे तक पड़ता है। चूंकि वे जीएसटी का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए इन पर इनपुट टैक्स की राहत भी नहीं मिलेगी और चूंकि खनिज उत्पाद विनिर्माण का अनिवार्य कच्चा माल हैं इसलिए उच्च कर की वजह से लागत में बहुत इजाफा देखने को मिल सकता है। चौथा, खनिजों पर कई प्रकार के कर लगाने से देश में विनिर्मित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होड़ करने लायक नहीं बचते। इससे उद्योग जगत आयात के जरिये देसी उद्यमियों पर निर्भरता घटा लेगा या ऊंचे कर के लिए समर्थन जुटाएगा। आयात शुरू करने पर खान बंद हो सकती हैं और नौकरियां जा सकती हैं। ऊंचे कर के लिए लामबंदी उपभोक्ताओं का ही नुकसान करेगी।

इस निर्णय का सबसे गंभीर प्रभाव पिछली तारीख से कर लगाने का अधिकार है। नीतियों में पिछली तारीख से लागू होने वाले बदलाव अर्थव्यवस्था को पहले भी अनिश्चितता की स्थिति में डाल चुके हैं, जिससे निवेश का माहौल बिगड़ा है। वोडाफोन कर मामले में हमारा अनुभव बुरा रहा है। पिछली तारीख से कर लगाया जाए तो निवेशकों के लिए अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। इकलौती उम्मीद यह है कि राज्य कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इस सामग्री पर भारी कर लगाने का नुकसान समझेंगे और बेहतर कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने की खातिर उन्हें पिछली तारीख से लागू करने से बचेंगे।

राजकोषीय प्रबंधन के लिए कार्य योजना जरूरी

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कुछ ही हफ्तों में पेश कर दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों की केंद्रीय बजट से अलग-अलग उम्मीदें हैं मगर इस स्तंभ में मुख्य रूप से बजट के इतर राजकोषीय प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य रखेगी। इसका मतलब है कि वह कोविड महामारी के बाद मध्यम अवधि के लिए तय लक्ष्य हासिल कर लेगी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मगर बहस इस बात पर है कि आगे क्या होगा। पिछले साल जुलाई में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2026-27 से सरकार हर साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इस तरह निर्धारित करेगी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार का घाटा कम होता रहे।

इस बारे में स्थिति और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। इस समय ऋण का बोझ बहुत है और उसमें जितनी जल्दी हो सके कमी लानी चाहिए। इसे देखते हुए अच्छा होगा यदि सरकार मध्यम अवधि की रणनीति और अंतिम लक्ष्य की जानकारी दे। कर्ज के बोझ को घटाते रहने से ही बात नहीं बनेगी। वित्तीय बाजारों और दूसरे हितधारकों को ऋण में कमी के लिए स्पष्ट योजना की और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजकोषीय घाटे के वांछित स्तर की जानकारी चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार पर कर्ज का बोझ वित्त वर्ष जीडीपी के 56.8 प्रतिशत के बराबर रहने का अनुमान है, जो 2023-24 में 58.1 प्रतिशत था। लेकिन यह भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति द्वारा 2017 में सुझाए गए स्तर से 17 प्रतिशत अधिक रहेगा। इस लेखक ने जुलाई 2024 में पेश बजट से पहले तर्क दिया था कि कोविड महामारी के बाद राजकोषीय स्थिति का सावधानी से अध्ययन होना चाहिए और यह काम विशेषज्ञ समिति करे तो बेहतर होगा। उसके बाद उपयुक्त राजकोषीय नीति तैयार की जानी चाहिए। कुल मिलाकर कोविड महामारी के बाद देसी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी बदलाव आने से राजकोषीय प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण सुधारों की जरूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा कुछ दूसरे पहलुओं पर भी विचार होना चाहिए।

अर्थतंत्र

राजेश कुमार

पहला महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है। पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष में बढ़कर जीडीपी का 3.4 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 1.67 प्रतिशत था। इससे देश की अर्थव्यवस्था को कोविड महामारी की मार से उबरने में मदद मिली है मगर सरकार को कहीं न कहीं अपनी उधारी जरूरतों को अर्थव्यवस्था की कर्ज लेने की क्षमता के हिसाब से ढालना होगा। वर्ष 2022-23 में शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत कम होकर जीडीपी की 5.3 प्रतिशत रह गई। हालांकि वित्तीय बचत वापस दीर्घावधि औसत तक पहुंच सकती है मगर सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी की जरूरत में वह आराम से खप जाएगी। इस समय अर्थव्यवस्था को कर्ज की दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि निजी क्षेत्र पर्याप्त निवेश नहीं कर रहा है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। अतः सरकार को बाहर से कर्ज में भारी इजाफा किए बगैर निजी क्षेत्र के लिए निवेश की गुंजाइश तैयार करनी चाहिए।

दूसरी बात, बाजार को यह भी पता होना चाहिए कि राज्य भी इसी व्यवस्था का अनुसरण करेंगे या नहीं। वर्ष 2023-24 में राज्यों पर कुल कर्ज जीडीपी के 28.5 प्रतिशत पर पहुंच गया था। यह आंकड़ा एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा सुझाए गए स्तर से 8 प्रतिशत अधिक था। भारत में सरकार पर सामान्य कर्ज और बजट घाटा चिंता और जोखिम की बड़ी वजह बना हुआ है। इसलिए आगे की स्पष्ट योजना होने से वित्तीय बाजारों का भरोसा बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

व्यापक राजकोषीय रणनीति तैयार करने के साथ ही आने वाले महीनों में कुछ विशेष उपाय भी करने पड़ेंगे। सरकार सीमा शुल्क के ढांचे और आयकर अधिनियम की भी समीक्षा कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि समीक्षा के बाद फौरन नीतिगत कदम उठाए जाएंगे या नहीं। अगले केंद्रीय बजट के अलावा जिन दूसरे नीतिगत उपायों पर नजर होगी, उनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संभावित बदलाव भी शामिल है। हालांकि इन बदलावों पर जीएसटी परिषद की मुहर लगनी जरूरी होगी मगर केंद्र सरकार इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

देश के कई राज्यों में राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार है इसलिए जीएसटी में सुधार के लिए कोशिश करना केंद्र सरकार के लिए तुलनात्मक रूप से आसान होगा। मंत्रियों के विभिन्न समूह दर को उचित बनाने एवं मुआवजा उपकर जैसे विषयों पर विचार कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान केंद्र ने राज्यों के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए कर्ज लिया था और उसे चुकाने के लिए ही मुआवजा उपकर वसूला जा रहा है। मुआवजा उपकर का लक्ष्य इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है और उसके बाद इसकी वसूली बंद हो जाएगी बशर्ते कोई कानूनी बदलाव न किया जाए।

चूंकि जीएसटी प्रणाली में कर और स्लैब (श्रेणी) को भी वाजिब बनाए जाने की जरूरत है, जिसके लिए मंत्रियों का समूह अध्ययन भी कर रहा है, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाए कि इसमें होने वाले बदलाव कम से कम उथल-पुथल लाएं। जीएसटी की औसत दर भी राजस्व निरपेक्ष स्तर तक लाई पहुंचाई जाए। हाल ही में संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि वर्ष 2023-24 में औसत जीएसटी दर 11.6 प्रतिशत थी, जो 2015 में तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई 15-15.5 प्रतिशत राजस्व-निरपेक्ष दर की तुलना में काफी कम थी।

समय से पहले दरें घटाना भी जीएसटी के कमजोर प्रदर्शन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उसके राजस्व में हुए नुकसान की तो भरपाई भी नहीं हो पाई। डॉ. सुब्रमण्यम और अन्य के अनुसार नुकसान सालाना जीडीपी के 0.6 प्रतिशत और 1.0 के बीच रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान मुआवजा उपकर सहित कुल संग्रह मोटे तौर पर जीडीपी का उतना ही प्रतिशत रहा, जो जीएसटी लागू होने से पहले वसूले जा रहे सभी करों से जुटा था।

जीएसटी में आवश्यक सुधार होने से कुछ हद तक कर्ज और राजकोषीय घाटे जैसी चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्षमता में भी इजाफा होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को विनिवेश कार्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए और इसे दोबारा पटरी पर लाना चाहिए। इससे पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर समझौता किए बिना राजकोष को दुरुस्त रखने में आसानी होगी।

आपका पक्ष

जीएसटी दरें कम हों, यही है एक मंत्र

लेख 'बदलाव के इंतजार में जीएसटी व्यवस्था' एक ही समाधान की ओर संकेत करते हैं कि जीएसटी की दरें कम की जानी चाहिए और विभिन्न टैक्स स्लैबों में अंतर भी कम हो। नीति निर्धारकों की कई गलतफहमियां हैं कि जीएसटी कर बढ़ा कर राजस्व संग्रहण बढ़ सकता है, लग्जरी माल पर अधिकतम दर 28 प्रतिशत से राजस्व संग्रहण में सरकार को कोई लाभ होगा और इनपुट टैक्स की रिफंड व्यवस्था दोषरहित हो सकती है। वित्त मंत्रालय को अपने दोनों राजस्व संग्रहण एक ही नीति और व्यवस्था के अंतर्गत संचालित करने चाहिए। जब इस वर्ष का बजट वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और विशेषज्ञों के विचार मंथन में है, तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बिंदु पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जीएसटी की ऊंची दरों के कारण जो व्यापार में कर अपवंचन होता है उसके कारण आयकर संग्रहण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उच्चतम जीएसटी दरें लग्जरी, कॉस्मेटिक, सीमेंट, फर्नीचर आदि पर लगता है, यह व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है और यह सभी आम जनमानस के उपयोग के लिए हैं। सीमेंट पर उच्च जीएसटी दरें रियलटी क्षेत्र के लिए हतोत्साहित करने वाली हैं। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि धनाढ्य और उच्च आय वाला वर्ग अधिकतम दर पर आयकर देता है तो फिर बार बार उच्च आय वर्ग को ही लग्जरी के नाम पर जीएसटी की उच्चतम दर से दंडित किया जाता है। कहने के लिए प्रत्यक्ष कर आयकर और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है परंतु इनकी सीधी देयता करदाता से ही है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

जीएसटी की ऊंची दरों के कारण व्यापार में जो कर अपवंचन होता है उसके कारण आयकर संग्रहण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है

संतुलित विकास का मार्ग

भारतीय अर्थव्यवस्था आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में खड़ी है। लेकिन, क्या यह प्रगति सतत और समावेशी है? आर्थिक विकास में निवेश और उद्योगों के विस्तार की भूमिका तो अहम है, पर ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है। भारत की जीडीपी दर में 2024-25 तक 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के बिना अधूरी है। आज भी ग्रामीण भारत की बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि-आधारित उद्योगों का विकास, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन और कौशल विकास कार्यक्रमों का व्यापक क्रियान्वयन आवश्यक है। शहरीकरण की तेज रफ्तार में भी योजनाबद्ध दृष्टिकोण की कमी दिखती है। मेट्रो शहरों में बढ़ते निर्माण परियोजनाएं के साथ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हरित तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। भविष्य की नीतियों में एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो निवेशकों के लिए अवसर प्रदान करे और आम नागरिकों को भी लाभान्वित करे। शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता में सुधार, साथ ही स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाना, आत्मनिर्भर भारत का असली आधार बनेगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अंतिम दिन त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू तथा 26 अन्य को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और विभिन्न क्षेत्रों में समाज के वास्ते काम करने के लिए उनकी सराहना की।

राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 11 जनवरी • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कर्म, ज्ञान और भक्ति-ये तीनों जहां मिलते हैं वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जन्म लेता है

-श्री अरविंद

'इंडिया' का अंतर्विरोध

दिल्ली विधानसभा चुनाव ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में आई दरार को और अधिक चौड़ा कर दिया है। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता अजय माकन के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को फर्जी वालों और राष्ट्रद्रोही बताया था। इसकी प्रतिक्रिया में आप ने कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की धमकी दी थी। अब तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना (उद्धव) ने आप को समर्थन देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोक सभा चुनाव के लिए ही था। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लोक सभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था, लेकिन लोक सभा चुनाव के दौरान वह

गठबंधन कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार नहीं कर सका और ना किसी को संयोजक ही बन सका। इसने राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभियान भी नहीं चलाया। हालांकि तथ्य यह है कि इसके बावजूद इंडिया गठबंधन भाजपा को लगातार तीसरी बार बहुमत पाने से रोक दिया। यह सच है कि क्षेत्रीय दलों के समर्थन से कांग्रेस लोक सभा में 99 सीटें पाने में सफल रही। इंडिया के घटक दलों का आरोप है कि कांग्रेस अपनी जीत का श्रेय गठबंधन को न देकर अपनी नीतियों और अपने नेता को दे रही है। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि कांग्रेस संसद में अपने दलीय हितों से जुड़े मसले को उठाती रही जबकि उसे अपने सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनानी चाहिए थी। इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस क्रम में सबसे पहले ममता बनर्जी ने सवाल उठाया और खुद नेतृत्व करने का दावा पेश किया और लालू यादव ने उनके सुर में सुर मिलाया। गठबंधन के घटक दल अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस को पांव जमाने का मौका नहीं देना चाहते। दूसरी ओर कांग्रेस भी जिन राज्यों में मजबूत है वहां इंडिया में शामिल क्षेत्रीय दलों से तालमेल करना नहीं चाहती। इसी अंतर्विरोध को देखते हुए उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि यदि गठबंधन केवल लोस चुनाव तक ही था तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस गठबंधन से भले अलग-थलग पड़ती जा रही हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि भाजपा को हराने के लिए जो भी विपक्षी गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस की प्रमुख भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

पद पर हावी राजनीति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें अब बिजनेसमैन, आईएएस व आईपीएस सरीखे अधिकारी भी विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकेंगे। इस चयन का अधिकार केवल चांसलर का होगा, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अभी तक शिक्षाविद के तौर पर दस का कार्यकाल आवश्यक था, परंतु अब वे इसके पात्र होंगे, जो संबंधित फील्ड के विशेषज्ञ, शोध, उद्योग व लोकप्रशासक का अनुभव हो, जिसमें दस साल काम किया हो तथा उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पहले भी सरकार पर उंगलियां उठती रही हैं। अब जब उद्योगपतियों व ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं तो चयन को लेकर और भी संदेह उपज सकते हैं। सत्तापक्ष के इशारे पर उसके वफादारों पर

पद बंटवारे की आशंकाओं से मुक्त नहीं रहा जा सकता। निःसंदेह उद्योगपतियों को कुलपति जैसे सम्मानित पद पर सुशोभित करने से आर्थिक लाभ मिलने की गुंजाइश बढ़ सकती है। जैसे कि ब्यूरोक्रेट अपने अनुभवों का बेहतरीन इस्तेमाल कर नये मार्ग इजात कर सकते हैं। मगर चयन समितियों के गठन पर उठने वाले सवालों को रोकना भी सरकार और यूजीसी की बड़ी जिम्मेदारी होगी। राज्यपाल उन्हीं सिफारिशों पर मुहर लगाता है, जो राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित होती हैं। उपने उम्मीदवार को कुलपति चुनने पर राज्यपालों की भी राज्य सरकारों से सीधा टकराव की स्थितियां देखने में आती रही हैं। चूंकि राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए वे विश्वविद्यालयों के प्रशासन में सीधी दखलंदाजी को आजाद हैं। नये नियमों की अवहेलना करने वाले विश्वविद्यालयों के प्रति यूजीसी का रवैया क्या हो सकता है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वहां विवाद की स्थितियों को रोकना नामुमकिन होगा। वे स्पष्ट रूप से इसे संघ का एजेंडा मानते हैं। जैसे कि केरल के मुख्यमंत्री ने शुरुआत ही इस मसौदे की आलोचना से की है। सरकार तथा आयोग को ऐसे सम्मानित पदों का शुद्ध राजनीतिकरण करने की बजाए दरम्याना रवैया इख्तियार करने का प्रयास करना होगा।

कटाक्ष/ कबीरदास

दुनिया के मजदूरो मशीन बनो!

अब कुछ भी कहे, एल एंड टी कंपनी वाले सुब्रमण्यम साहब की बात में हमें तो दम नजर आता है। सिंपल सी बात है। इतवार की छुट्टी यानी सोमवार, मंगवार, बुधवार, चूहस्पतिवार...किसी भी दिन की छुट्टी की मजदूरों-कर्मचारियों को जरूरत ही क्या है? बिल्कुल टाइम वेस्ट। घर पर बैठकर बीवी का चेहरा ताकते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो; यह भी कोई करने वाला काम है। इससे अच्छा तो सातो दिन, बारहो महीना कारखाने, दफ्तर में काम करो। पैदावार ज्यादा तो मुनाफा भी ज्यादा और जीडीपी भी ज्यादा। और जीडीपी ज्यादा तो सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा। यानी मालिक भी खुश और निर्मला ताई भी खुश। सिर्फ बीवी को खुश करने के चक्कर में देश की जीडीपी क्यों डुबो रहे हैं ये मजदूर-बजदूर।

इतनी अक्ल की बात करने में सुब्रमण्यम जी अकेले नहीं हैं। उनसे पहले इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति जी भी यही एडवाइज दे चुके थे। वस बो इतवार बगैरह की छुट्टी के चक्कर में नहीं पड़े थे और सीधे प्वाइंट पर आ गए। दिन में काम के घंटे कम से कम वाहर-चौदह तो होने ही चाहिए। और वह देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी की फॉलो कर रहे थे। जब नारायण मूर्ति की कान में यह बात पड़ी कि मोदी जी दिन में अठारह-अठारह घंटे काम करते हैं, तो एकदम से उन्हें बोध प्राप्त हो गया। यही तो सारी समस्याओं का समाधान है, सारे रोगों की रामबाण औषधि है। सब ज्यादा घंटे काम करें, दो खुद व खुद आगे बढ़ जाएगा। सुब्रमण्यम जी ने गेंद और आगे बढ़ा दी। सवाल उनकी कंपनी में शनिवार की छुट्टी नहीं देने पर पूछा गया था, उन्होंने इतवार की छुट्टी को भी नजर लगा दी। सुब्रमण्यम साहब, मूर्ति साहब, मोदी साहब लोगों की बदकिस्मती से, इन मजदूरों-बजदूरों के साथ एक बड़ी प्राब्लम है। जब तक काम नहीं मिलता तब तो फिर भी ठीक रहते हैं, पर काम मिला नहीं कि ये खुद को इंसान समझने लगते हैं। खुद को तो खुद को, अपनी बीवी, बच्चों को भी इंसान समझने लगते हैं। उनकी तरफ इंसानों की नजर से देखने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मिडास मंतर से सारे मेहनत करने वालों को मशीन बना दिया जाए? न कोई बीवी को निहारते बैठेगा और न छुट्टी के नाम पर किसी भी दिन की बर्बादी होगी। मजदूरी की झिकझिक भी खत्म।

सुस्त होती रफ्तार

हाल ही में 7 जनवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कहा कि जीडीपी के इस वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में देखी गई 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि से काफी कम है। ज्ञातव्य है कि पिछले चार वर्षों में और कोविड के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि का यह सबसे निचला स्तर है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने क्विकास अनुमान को 7.2 प्रतिशत के पहले के अनुमान से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है।

जब हम जीडीपी वृद्धि दर में हालिया सुस्ती के कारण पर विचार करें तो पाते हैं कि बीते वर्ष 2024 कई आर्थिक चुनौतियों के कारण जीडीपी में सुस्ती आई है। वैश्विक भू राजनीतिक कारणों और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने विकास दर को प्रभावित किया है। ऊंची ब्याज दर व खपत में कमी का भी प्रभाव पड़ा है। यद्यपि बीते वर्ष 2024 की शुरुआत 8 फीसद विकास दर के साथ हुई थी, लेकिन बीते वर्ष की जुलाई से सितम्बर की तिमाही में महज 5.4 फीसद की विकास दर के कारण कई आर्थिक गणित गड़बड़ा गए। बीते वर्ष में भारत के आर्थिक परिदृश्य पर प्रमुखतया महंगाई तथा रोजगार चिंताजनक मुद्दे रहे हैं।

महंगाई के मोर्चे पर मुश्किलें लगभग अधिकांश महीनों में बनी रहीं। खासतौर से नवम्बर 2024 के बाद एक बार फिर थोक एवं खुदरा महंगाई बढ़ने लगी और महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित दायरे से बाहर रही। बीते वर्ष में यद्यपि शहरी बेरोजगारी में कमी आई, लेकिन असंगठित सेक्टर में रोजगार के मौके घट गए। बीते वर्ष में विदेश व्यापार घाटा भी बढ़ा। बीते हुए वर्ष में रुपया वर्षभर लुढ़कता रहा। वर्षभर डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत घटती गई और दिसम्बर 2024 में डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़ककर 85 से भी नीचे के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2024 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई । दिसम्बर 2024 में विदेशी मुद्रा कोष घटते हुए करीब 652 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि जीडीपी में बड़ी कमी आई है, लेकिन नये वर्ष 2025 को पिछले बीते वर्ष से आर्थिक विकास के ठोस आधार भी मिले हैं, जिनसे अनुमानित विकास दर बढ़ सकती है। अर्थविशेषज्ञ एक मत से कारोबारी और वित्तीय ऊंचाई को लेकर आशावादी हैं और वे विकास मूलक संकेत देते हुए देश की मजबूत वैलेंस शीट प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कृषि,

जीडीपी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

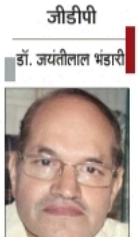

खनन, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन को तेज रफ्तार मिलेगी। नई डिफ्रेशिय व्यापार बातीएं व नये मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) आकार लेते हुए दिखाई देंगे। खासतौर से सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, ट्रांसपोर्ट, ऑटो मोबाइल, फॉर्मा, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, सायबर सिक्योरिटी, आईटी, ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेड, आदि क्षेत्रों में तेज विकास होगा। इससे रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नये वर्ष 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे।

चूंकि देश में जीडीपी की रफ्तार घटने के बाद अब निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक माहौल अनुकूल होता नहीं दिखता, इसलिए घरेलू नीतियों से वृद्धि को गति देना होगी। नये वर्ष 2025 में जीडीपी की सुस्त रफ्तार को बढ़ाने में स्थानीय और घरेलू बाजार की मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगी। पिछले 10 साल में देश जिस तेजी से आत्मनिर्भरता की नीति और 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ आगे बढ़ा है, उससे नये वर्ष में देश अधिक लाभान्वित होगा। 'डेलॉइट इंडिया' की इंडिया होम एंड हाउसहोल्ड मार्केट प्रिपेयर्ड कहा गया है कि भारत का घरेलू बाजार 10 फीसद से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। निश्चित रूप से नये वर्ष में देश के कोने-कोने में 'मेक इन इंडिया' अभियान की शक्ति बढ़ेगी। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष बंपर खरीफ और रबी फसल की संभावनाओं के कारण खाद्यान्न की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। इससे वर्ष 2025 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

देश में कृषि उन्नयन, खेती में नवाचार को प्रोत्साहन देने, लागत को कम करते हुए उत्पादन के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने का अभूतपूर्व अभियान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकेगा। इसमें कोई दोमत नहीं है कि सरकार को बीते हुए वर्ष से जो बेहतर मानसून बिरासत में मिला है, उससे नये वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों में खपत भी बढ़ेगी। देश में कृषि क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ेगा। ज्ञातव्य है कि फसल वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 32.22 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2023-24 में गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन हुआ है। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन 1132.92 लाख टन और चावल का उत्पादन 1378.25 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया। यह अनुमान किया गया है कि सरकार की नई कृषि विकास रणनीति से नये वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा और जीडीपी बढ़ेगी।

नये वर्ष में सरकार को बेहतर संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। भारतीय शेयर बाजार को राह कठिन नहीं होगी, शेयर बाजार को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाने में घरेलू फंड की अहम भूमिका होगी और कारपोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसी माह जनवरी 2025 में ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका द्वारा चीन पर भारी व्यापार प्रतिबंधों की संभावना से भारत के नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश बनने की संभावना बढ़ेगी। देश बनने की संभावना बढ़ेगी। हम उम्मीद करें कि 7 जनवरी को एनएसओ के द्वारा जारी जीडीपी की सुस्त रफ्तार के आंकड़ों के मद्देनजर नये वर्ष 2025 में सरकार के द्वारा ब्याज दर में कमी, आर्थिक और वित्तीय सुधारों, कृषि सुधारों, मेक इन इंडिया, निर्यात बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ाने के रणनीतिक प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील किया जाएगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

> नये वर्ष में सरकार को बेहतर संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। भारतीय शेयर बाजार की राह कठिन नहीं होगी, शेयर बाजार को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाने में घरेलू फंड की अहम भूमिका होगी और कारपोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसी माह जनवरी 2025 में ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका द्वारा चीन पर भारी व्यापार प्रतिबंधों की संभावना से भारत के नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश बनने की संभावना बढ़ेगी

प्रीतीश नंदी के निधन की दुखद खबर मिली। नामी संपादकों के दौर में वे बड़ा नाम थे। पत्रकार तो थे ही, ऐसे व्यक्तित्व भी थे जो कविता और सिनेमा पर भी सहजता से वतिया लेते थे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विचारों से हर किसी को हतप्रभ कर देने वाले प्रीतीश नंदी इस अंदाज में जीए कि मुझे पसंद करो या न करो लेकिन मुझे नजरंदाज नहीं कर सकते।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

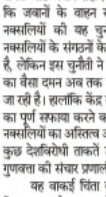

सरकार को मिली निर्णायक सफलता

नक्सली गतिविधि | प्रमोद भार्गव

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला मुख्यालय से 55 किमी दूर अंबेली गांव के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गए अति तीव्र विस्फोटक की चपेट में आकर एक आरक्षित गार्ड समेत आठ जवान शहीद हो गए। विस्फोटक इतना तीव्र था कि जवानों के वाहन स्कार्पियों के परखच्चे उड़ गए। नक्सलियों की यह चुनौती उस समय मिली है, जब नक्सलियों के संगठनों के खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस चुनौती ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों का वैसा दमन अब तक नहीं हो सका है, जैसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया करने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन नक्सलियों का अस्तित्व अब तक बना है तो इसलिए क्योंकि कुछ देशविरोधी ताकतें उन्हें धन, विस्फोटक और उत्तम गुणवत्ता की संचार प्रणाली उपलब्ध करा रहे हैं।

यह वाकई चिंता का विषय है कि नक्सली अपने विरुद्ध चल रहे सुरक्षाबलों के अभियानों को निशाना बनाने में बार-बार क्षति पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। अतएव लगता है कि बनवासियों और ग्रामीणों पर उनकी पकड़ अभी भी बनी हुई है। वहीं सुरक्षाबलों की मुखबिरी करके सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार को कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं।

केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। शाह का कहना है कि 2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004-14 में नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10

वर्षों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004-14 में 6,568 थी, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई है और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सालियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं और इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाका है, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लाना पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों, छिपने के स्थलों और जल सोतों से भी ये खुब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है।

जब किसी भी किस्म का चरमपंथ राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बन जाए तो जरूरी हो जाता है, कि उसे नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कारगर उपाय उचित हों, उनका उपयोग किया जाए? हालांकि देश में तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब वे राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, लेकिन अब इस चरमपंथ पर अंकुश लगाना जरूरी है।

आत्मा की पुकार | संत राजिन्दर

हमारे शरीर में मन के अलावा आत्मा भी निवास करती है। हम अपना जीवन जीते हुए शरीर और मन की जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें पूरी भी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है? हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते उनसे बिछड़ चुकी है और वह चाहती है कि वह हमेशा-हमेशा के लिए प्रभु में जाकर समा जाए।

चौरासी लाख योनियों में केवल मानव चोले में ही वह प्रभु से एकमेक हो सकती है, इसलिए वह यह चाहती है कि हम इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। जब हम अपनी आत्मा की इस करुण पुकार को सुनते हैं, तब प्रभु हमें वह रास्ता दिखा देते हैं जहां से कोई हमें प्रभु के निजधाम वापस ले जा सकता है। प्रभु हमें वक्त के संत-सतगुरु से मिला देते हैं जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हैं जोकि परमात्मा का ही अंश है। फिर वे हमें एक ऐसी विधि सिखाते हैं जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार में रहते हुए स्वयं के असली स्वरूप को जान सकते हैं। संत-सतगुरु हमें हमारे असली स्वरूप को जानने और पिता-परमेश्वर से एकमेक होने के लिए ध्यान-अभ्यास की विधि सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ध्यान-अभ्यास के द्वारा अपने ध्यान को अंतर की दुनिया में लेकर जाएं? वे हमारा संपर्क प्रभु की 'ज्योति' और 'श्रुति' की धारा से कराते हैं, जिसे 'नाम' भी कहा गया है। चेतनता की इस धारा के जरिये ही प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की। जब हम ध्यान-अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु की इस धारा के संपर्क में आती है जिसके द्वारा हम पूर्ण संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं और फिर जिसके सामने इस संसार के सभी भौतिक आनंद हमें फीके और क्षणभंगुर लगने लगते हैं। प्रभु की यह धारा हमें प्रभु से एकमेक कराती है और साथ ही साथ उनसे उत्पन्न प्रेम की शक्ति का भी अनुभव कराती है। हम इस संसार की किसी भी अन्य वस्तु से वैसी संतुष्टि नहीं पाते जितनी हम ध्यान-अभ्यास के दौरान 'ज्योति' और 'श्रुति' के संपर्क में आ जाने से पाते हैं। हमारी आत्मा जब एक बार उस परमानंद को पा लेती है तो उसे बार-बार पाना चाहती है और उस अविरल धारा में अधिक से अधिक लीन रहना चाहती है।

रीडर्स मेल

महाकुंभ में सावधानी जरूरी

महाकुंभ मेले के इस दिव्य आयोजन में जनसंकुल के मध्य सुरक्षा और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। भीड़भाड़ में संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों और निर्देशों का पालन करना जरूरी है। पहचान पत्र, मोबाइल, और आवश्यक दस्तावेज सदैव अपने पास रखना होगा। परिवार या समूह से संपर्क बनाए रखें और बिछड़ने की स्थिति में पूर्व निर्धारित स्थान पर मिलें। आरामदायक वस्त्र धारण करें और मौसम के अनुसार तैयारी करें। कीमती सामानों को सुरक्षित रखें और केवल स्वच्छ व प्रशासन द्वारा अनुमोदित भोजन-पेय का सेवन करें। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है, आपातकालीन सेवाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी हरेक को रखनी चाहिए। भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचते हुए श्रद्धा के साथ अलौकिक आयोजन का अनुभव करें। धैर्य, शांति, और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि कुंभ का यह आध्यात्मिक महासंगम स्मरणीय बने।

रोहित सोलंकी, ई मेल से

तालिबान सरकार से मित्रता

भारत के विदेश सचिव के साथ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री की दुबई में हुई मीटिंग वाकई कई मायनों में अहम है। बैठक में मानवीय सुरक्षा, शरणार्थियों के पुनर्वास, खेलों के प्रोत्साहन और चाबहार पोर्ट पर व्यापारिक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दुनिया जानती है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा सदियों पुरानी है। पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित करने से न केवल दो मुल्कों की तरक्की का रास्ता खुलता है बल्कि इससे पूरी दुनिया के लोगों को भी लाभ मिलता है। अफगानिस्तान में इस समय तालिबानी शासन चल रहा है जिसे भारत ने भले ही अभी मान्यता प्रदान नहीं की हो, परंतु फिर भी हमने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई इस बातचीत में अफगानिस्तान ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं कि वो भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बात भी सही है कि इस समय अफगानिस्तान के पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है। पिछले दिनों दोनों मुल्कों के बीच झड़पें भी हुई थी। लहरहाल, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई बैठक को शांति और विकास की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है।

हितेंद्र डेड़ा, दिल्ली

कार्रवाई करे सरकार

शेयर बाजार धन वृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम है, लेकिन फर्जी एडवाइजरी केंद्र निवेशकों के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। ये केंद्र असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को भ्रमित करते हैं। अपनी पहचान प्रमाणित दिखाने के लिए वे खुद को पंजीकृत संस्थान बताते हैं और बैंक खाता व पैन कार्ड जैसी जानकारी मांगते हैं। अग्रिम शुल्क वसूलकर वे राशि गबन कर लेते हैं या नुकसानदायक निवेश में लगा देते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे फर्जी केंद्रों पर सख्त कार्रवाई करे और जागरूकता अभियान चलाए। केवल सेबी पंजीकृत सलाहकारों पर भरोसा करें, सतर्क रहें, और अपनी जानकारी सुरक्षित रखें।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी, मप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा हैडिक पत्र कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 145
अर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी पहलुओं के लिए उत्तरदायी

1.55 करोड़ मतदाताओं की संख्या है दिल्ली में, जिनमें 83.5 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 71.7 लाख है।

मनु त्यागी
manu@nda.jagran.com

आजकल

मुख्य मुद्दों से भटक रहा दिल्ली चुनाव

दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ रहा है। परंतु इन सबके बीच दिल्ली के मुख्य मुद्दों पर बातें कम ही हो रही हैं। अधिकांश चर्चा मतदाताओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाए जाने से संबंधित योजनाओं की ही हो रही है, जिसे 'रेवड़ी' के रूप में जाना-समझा जाता है। ऐसे में मुख्य मुद्दों से भटकाव दिल्ली और दिल्लीवासियों के लिए चिंता का विषय है, जिसे समय रहते समझा जाना चाहिए

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, परंतु ऐसा लग रहा है कि विकास का मुद्दा सभी दलों के लिए गौणहै। फाइल

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान तिथि की घोषणा की जा चुकी है। पांच फरवरी को दिल्ली के मतदाता नई सरकार के गठन हेतु वोट डालेंगे। लेकिन, क्या दिल्ली वाले अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे? आखिर दिल्ली के साथ न्याय कौन करेगा, उसके मुद्दों की बात कौन करेगा? उसकी तकलीफों को कौन समझेगा? यदि दिल्ली गंभीरता से सोचे तो ये सवाल बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। बशर्ते दिल्ली उस दृष्टिकोण से सोचे, क्या दिल्ली देश की राजधानी है और जहां प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से अधिक है, उसके लिए 'रेवड़ियों' वाली दिल्ली' या चुनावी घोषणाओं वाली दिल्ली जैसा तमगा कैसा महसूस कराता है।

देखा जाए तो दिल्ली के लोगों की परिशानियों की चिंता किसी को नहीं है। पीने के पानी से लेकर सड़कों की दशा बहुत ही खराब है। वायु गुणवत्ता लगभग पूरे साल खराब श्रेणी में रहती है। विधानसभा चुनाव के दौर में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई तो देश के दिल को बचाने की बात करेगा। वैश्विक पटल पर दिल्ली के माथे पर लगे प्रदूषण के दाग को मिटाने का संकल्प लेगा। रेवड़ी, चुनावी घोषणा, रिझाना, मनाना इससे आगे कोई खालिस दिल्ली की बात करेगा। कहें तो, दिल्ली इंतजार कर रही है कि कोई उसके 'दिल का हाल सुने दिल वाला' मिलेगा। अब राजनीति तो अपनी कुटनीति से ही चलेगी।

चरमराता चुनियादी ढांचा : बगैर सोचे-समझे लालसाओं की परवरिश में बेहिसाब या कहें कि बेतरतीब रूप में बढ़ रही दिल्ली में जहां 90 लाख की ही आबादी होनी चाहिए, वहां अब आंकड़ा तीन करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली वाली पहचान 'वोट बैंक' भी डेढ़ करोड़ मतों से मजबूत हो रहा है। उसके मुद्दों की बात भी तो होनी चाहिए। प्रदूषण जिसे अब तक भी केवल तीन माह में 'ग्रेप लगाओ-ग्रेप हटाओ' की खानापूरी से देखा जाता है, उसके लिए कोई राजनीतिक दल तो 12 माह दिल्ली की वैश्विक पटल पर बन रही 'खराब छवि' सुधारने के लिए घोषणा करे। दिल्ली की आर्थिकी तक इससे कराहती है। साल भर इस पर आरोप-प्रत्यारोप चलता है, परंतु जब चुनाव आते हैं तो सब इस पर मौन होते हैं। दिल्ली में केवल नई दिल्ली वाले हिस्से में सबकुछ ठीकठाक दिखता है, जिसे लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। शेष दिल्ली में आप जहां कहीं भी जाइए, वहां आपको शहरी ढांचा, सड़क, सब किसी ऊबड़-खाबड़ जैसी तस्वीर वाला ही नजर आएगा।

किसी को नहीं यमुना की चिंता : अब बात पानी की। मुफ्त पानी, 24 घंटे पानी दिल्ली को सूझ रहा है, लेकिन दिल्ली की उन तस्वीरों का क्या, जिनसे अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी छवि धूमिल होती है कि यह भारत की राजधानी दिल्ली है, जहां पानी के लिए कतार लगती है और सैकड़ों कच्ची बालोनियों में टैंकरों से पानी आपूर्ति होती है यानी वहां पानी की पाइपलाइन तक नहीं है। भला हम मुफ्त किसे दे रहे हैं? यह सवाल तो मतदाता के कीमती वोट का ही बनता है। गर्मी में सूखा और बरसात आते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसे रहेजने के लिए कोई प्राकृतिक संयंत्र नहीं है। देश की राजधानी के लिए माथे पर कलंक तो इस बात का भी है कि उसमें एक बड़ी नदी दम तोड़ने की अवस्था में पहुंच चुकी है। सब उसमें मौसमी डुबकी की तो बात करते हैं, लेकिन कोई उसे उसके पुराने रूप में लाने के बारे में कुछ ठोस करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। दिल्ली का शिक्षा 'माडल' भी अब युवा वाली बात करने वाला होना चाहिए, कोई तो युवा मतदाता के लिए रोजगार के अच्छे रोडमैप एजेंडे में लेकर चुनावी मैदान में आए, दिल्ली प्रतीक्षा में है।

जनकल्याण बनाम हानिकारक 'रेवड़ी' : मुद्दों से इतर चुनावी प्रलोभनों और रेवड़ी घोषणाओं का पिटारा खुला ही हुआ है। अब तक रेवड़ी प्रलोभन का पलड़ा ही भारी है। इसीलिए राजनीतिक दल एक-दूसरे की घोषणाओं का वजन तौलकर अपनी योजना में कुछ वजन बढ़ाकर जनता के बीच 'कुछ अलग', कुछ हटकर करने वाले लुभावने एटीट्यूड के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। जनता अंदर ही अंदर गुरगुरा रही है, क्योंकि जागृति के अभाव में वह अपने दैनों ही हाथों में लड्डू देख रही है। महिला हैं तो, बुजुर्ग हैं तो, सभी के लिए कुछ न कुछ 'आफर्स' हैं। मतदाताओं की सूची में जिसका जितना अधिक वर्ग है, उसके लिए दलों ने उतना ही बड़ा प्रलोभन दिया है। इसके लिए राजनीतिक दल कितने बड़े हितैषी बने रहे हैं कि ये प्रलोभन और रेवड़ी नहीं जनकल्याण योजनाएं हैं। लेकिन जनकल्याण के इतिहास और वास्तविकता को कैसे बदला जा सकता है। जब समाज सुधार और सभी न्यूनतम आय वर्ग वालों के लिए जनहित वाली योजनाएं होती थीं। अब आप टैक्स भी अदा करते हैं और दिल्ली की सरकारी बसों में 'मुफ्त' सफर भी करते हैं तो भला इससे कौन सा जनकल्याण होगा।

इस समय राजनीतिक दलों ने दिल्ली में 2100 से लेकर 2500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने की जो भी प्रलोभनी घोषणा की है, यह उनके लिए तो ठीक लगती है, जो महिलाएं वास्तव में घर चलाने के लिए जूझती हैं, परंतु क्या उससे इतर सशक्तीकरण की दहलीज पर खुदको संबल के साथ खड़ा करने वाली या कोई से कैश मिलाकर खड़े होने वाली महिला वर्ग सोचे कि क्या प्रतिमाह इस तरह दी जाने वाली राशि उनके 'सशक्तीकरण के स्वाभिमान' को चोट नहीं पहुंचाती। यहां जनहित, जनकल्याण की परिभाषा को राजनीतिक दलों द्वारा अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर उससे वोट बंटोरने का प्रचलन देश की आर्थिकी के लिए तो नुकसानदाई होगा ही, वर्ष 2047 के स्वर्णिम भारत के सपने को भी ये प्रवृत्ति ठेस पहुंचाएगी।

भाजपा अपने पथ से डिगी नहीं है, अब विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध शीशमहल से शराब तक सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। मुफ्त की घोषणाओं से दिल्ली को नुकसान उन 'रेवड़ियों' के सच को सामने रख रही है। यह बात अलग है कि भाजपा स्वयं भी इस घेरे में है कि वह दिल्ली वालों के दिल में किसे बैठाएगी, कोई चेहरा तो बताए। और कहीं न कहीं यह भी सच है कि इस समय भाजपा के पास तीन दशक पहले खोई सत्ता वापस लेने की उस समयवाला जैसा मजबूत अनुभवी चेहरा भी नहीं है। भाजपा 27 साल के सूखे को खत्म तो करना चाहती है, लेकिन यह तो पार्टी को विचार करना ही होगा कि इस बार भी चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली के चुनावी मैदान में है। एक दौर था जब दिल्ली में मदनलाल खुराना जैसे स्थानीय नेता थे। अब आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में भाजपा केंद्र से मिले मार्गदर्शन पर तो आगे बढ़ती है, देश की राजधानी के नाते उसका दायित्व भी बनता है, फिर भी दिल्ली की जड़ों तक और दिल्ली तक तो प्रदेश भाजपा को खुद भी जगह बनानी होगी।

अब बात करते हैं इस चुनाव में सबसे अहम किरदार की तरह दिख रही कांग्रेस पार्टी की। जिसकी शीला दीक्षित के समय में एक गहरी छाप रही। उस दौर को दिल्ली आज भी याद करती है। एक बार यह पार्टी सत्ता से गई तो आपसी महत्वाकांक्षी खींचतानों में पार्टी स्वयं को एक दशक में भी नहीं उठा पाई। बड़े-बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस बीते दो चुनावों में लड़ी ही नहीं, सिर्फ एक 'नई पार्टी' जैसी भूमिका में उपस्थिति सी ही दर्ज कराती रही। कांग्रेस का जनाधार भी इसका गवाह है जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में महज चार प्रतिशत पर ही सिकुड़ गया था। इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को इस तरह 'हलके' में नहीं ले सकते। इस बार कांग्रेस अपने बूते ही लड़ाई में भी दिख रही है। इससे सबसे अधिक बेचैनी बढ़ती है आम आदमी पार्टी को। क्योंकि दिल्ली का हर राजनीतिक विश्लेषक यही कहता मिलता है कि आम आदमी पार्टी के पास सबसे मजबूत कांग्रेस का ही जनाधार है। मध्य वर्ग तक का मतदाता इस दल का 'पूर्व मतदाता' कहा जा सकता है। अब कांग्रेस इसी वर्ग में स्वयं को मजबूत कर रही है। चुनावी मौसमों में होने वाले दलों के गठबंधनों की गांठ भी खुल चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी बेमन से ही दोनों दल दिल्ली में साथ थे, अब तो खुलकर पस्त करने के इरादे से हैं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत प्राप्त होगा, यह तो जीत के जनादेश के एक माह बाद यानी आठ फरवरी को ही स्पष्ट होगा।

(मनु त्यागी)

कांग्रेस की सक्रियता बढ़ा रही 'आप' की बेचैनी

अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की राजनीति में उतरे थे तो एक भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का संकल्प लेकर आए थे। परंतु दूसरे विधानसभा का कार्यकाल शुरू होते ही उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। जेल से लौटने पर जनता के बीच विश्वास जगाने के लिए 'कट्टर ईमानदार' वाले 'बैनर' के साथ उन्हें उतरना पड़ा। दिल्ली की 'कुर्सी' भले कम 'पावर' वाली है, राज्यों सा अधिकार नहीं रखती है, लेकिन राजधानी के नाते देश में एक बड़ा संदेश देती है। यहां की सत्ता हासिल करना और उस पर बने रहना, अपने आप में मुख्य राजनीतिक दलों के लिए हमेशा साख का विषय रहा है। लेकिन, भ्रष्टाचार मुक्त करने के जुमले से जन्मी आम आदमी पार्टी अब तक का कार्यकाल पूरा करने के बाद, उसके लिए इस बार की जीत 'राष्ट्रीय प्रतिष्ठा' का सवाल है। एक कहावत है न उसके लिए उसे साम, दाम, दंड, भेद जो भी लगाना पड़ा तो वो करेगी। सत्ता में काबिज सरकार की स्थिति को देखेंगे तो भाजपा ने इसे 'भ्रष्टाचार वाली सरकार' से पुरजोर 'टेंट' देने की कोशिश की है। नगर निगम के चुनाव को यात कीजिए, भाजपा यहां भी आप सरकार के भ्रष्टाचारों को ही कभी आबकारी नीति तो कभी मोहल्ला क्लीनिक जैसे आरोपों को उजागर कर रही थी।

भाजपा अपने पथ से डिगी नहीं है, अब विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध शीशमहल से शराब तक सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। मुफ्त की घोषणाओं से दिल्ली को नुकसान उन 'रेवड़ियों' के सच को सामने रख रही है। यह बात अलग है कि भाजपा स्वयं भी इस घेरे में है कि वह दिल्ली वालों के दिल में किसे बैठाएगी, कोई चेहरा तो बताए। और कहीं न कहीं यह भी सच है कि इस समय भाजपा के पास तीन दशक पहले खोई सत्ता वापस लेने की उस समयवाला जैसा मजबूत अनुभवी चेहरा भी नहीं है। भाजपा 27 साल के सूखे को खत्म तो करना चाहती है, लेकिन यह तो पार्टी को विचार करना ही होगा कि इस बार भी चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली के चुनावी मैदान में है। एक दौर था जब दिल्ली में मदनलाल खुराना जैसे स्थानीय नेता थे। अब आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में भाजपा केंद्र से मिले मार्गदर्शन पर तो आगे बढ़ती है, देश की राजधानी के नाते उसका दायित्व भी बनता है, फिर भी दिल्ली की जड़ों तक और दिल्ली तक तो प्रदेश भाजपा को खुद भी जगह बनानी होगी।

अब बात करते हैं इस चुनाव में सबसे अहम किरदार की तरह दिख रही कांग्रेस पार्टी की। जिसकी शीला दीक्षित के समय में एक गहरी छाप रही। उस दौर को दिल्ली आज भी याद

खरी-खरी

आचार संहिता लागू हो गई है

पूरन सरमा

चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मैं खुशी से पागल हो गया हूं कि चलो अब कोई अवैध कार्य नहीं होगा। न तो कोई अपराधी चुनाव में खड़ा हो पाएगा, न ही भारत निर्वाचन आयोग की खर्च सीमा से ज्यादा खर्च होगा और न ही कोई चुनाव के संबंध में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होगी। न अब मतदान केंद्रों पर कब्जा होगा और न ही चुनाव में धर्म, जाति अथवा भाषण के आधार पर कोई चुनाव प्रत्याशी राजनीति कर पाएगा। अब चुनाव पूरी तरह से वैध तरीके से संपन्न होंगे।

ऐसा लग रहा है जैसे आचार संहिता लागू होते ही देश में समाजवाद आ गया है। अब केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जनता की कोई राहत की घोषणा करके उसे लुभा भी नहीं पाएगी। राजनीति में एकदम अनुशासन आ गया है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन ही इस देश की बुनियाद है। यही कारण है कि चुनाव आचार संहिता, जिसमें एक ऐसी गंध समाहित है, जिससे राष्ट्र एक अद्भुत वातावरण में दिन-रात नहा-धो रहा है।

आशेष पूरी तरह चौकस है। उसे पता चल गया कि फलां जगह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अविलंब कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए राजनीति में तमाम असामाजिक तत्वों की जुबान पर ताला जड़ गया है। बताइये यदि चुनाव आचार संहिता नहीं होती तो चुनाव में क्या होता? प्रत्याशी मनमाना पैसा व्यय करते यानी निर्धारित खर्च सीमा से 50 गुना तक अधिक खर्च करते। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर वोट मांगते।

वैसे चुनाव में खर्च हुए धन का प्रत्याशियों को हिसाब देना पड़ेगा। इतनी बहिया बात और क्या हो सकती है। हिसाब इतना माकूल देंगे कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। यदि उल्लंघन किया तो मामला न्यायालय में जाएगा और जब तक उस पर सुनवाई होगी, तब तक वह अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा अथवा वह न्यायिक फैसले में निर्दोष पाया जाएगा तथा याचिका खारिज कर दी जाएगी।

पोस्ट

कांग्रेस के नवनिर्मित मुख्यालय का नाम रखा गया है-इंदिरा भवन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल या डा. आंबेडकर एक बार फिर से बिसार दिए गए। सुमंत@sumantkabir

भारत का राजनीतिक वर्ग वोटों की खातिर देश की आर्थिक स्थिरता की बलि चढ़ाने को तैयार है।
कमलेश सिंह@kamleshksingh

ब्रिटिश पाउंड फिर गिरने लगा है, क्योंकि आय बढ़ नहीं रही और सरकार कर्ज लेकर खर्च कर रही है। कर्ज देने वाले ने कर्ज के लिए ऊंचा ब्याज मांगना शुरू कर दिया है। कर्ज महंगा होने पर मुद्रा सस्ती होने या गिरने लगती है। इसी तरह भारत में रुपया भी वोट के लिए मुफ्त बांटने की होड़ से गिर रहा है। शिव कांत@shivkant

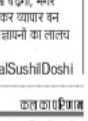

टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम का अर्थ है भारत, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया एक-दूसरे के खिलाफ ज्यादा टेस्ट खेलेंगे। मुकाबले बड़े एवं कड़े जरूर होंगे और टेस्ट में दिलचस्पी भी बढ़ेगी, मगर क्रिकेट सदभावना से हटकर व्यापार बन जाएगा। गेट मनी और विज्ञापनों का लालच ही इसके पीछे है।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों की आपत्तियां उचित हैं?

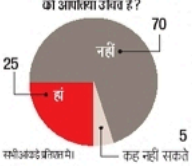

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम लागू करने का सुझाव सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मतहै।

जनपथ

सारे साथी छोड़कर कांग्रेस का 'हाथ',
खुल्लमखुल्ला दे रहे सिर्फ 'आप' का साथ।
सिर्फ 'आप' का साथ कांग्रेस रही अकेली,
आपस में ही बांट रहे सब गुड़ की भेली!
हैं ये कैसे दोस्त राज्य जैसे दो हारे,
राहुल जी को छोड़ भगे अब साथी सारे!!
- ओमप्रकाश तिवारी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार डायरी

चमत्कार से ही संभव तीसरे मोर्चे का गठन

बिहार के राजनीतिक दलों को यदि विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से देखें तो यही पता चलेगा कि चुनाव आजकल में होनेवाला है। एनडीए के सभी घटक दल मैदान में कूद पड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। घटक दलों के नेता-कार्यकर्ता जिलों में सप्ता सम्मेलन की तैयारी में जुटे हैं। सरकार की योजनाओं का नियोजित ढंग से प्रचार-प्रसार हो रहा है, ताकि लोग हमेशा याद रखें। दूसरी तरफ महागठबंधन में केवल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेस का कोई राज्यव्यापी कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सहयोगी वाम दलों की गतिविधियां नियमित ढंग से ही चल रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अलग से उनकी तैयारी नजर नहीं आ रही है।

वैसे चुनाव के समय गठबंधन के घटक दलों में अक्सर सीटों को लेकर मारामारी हो जाती है। कुछ घटक दल नाराज होकर अलग हो जाते हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ ऐसा हो चुका है। उस समय विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी सीटों की कम संख्या को लेकर अलग हो गए थे। यह अलगाव सीटों के बंटवारे के लिए हो रही बैठक में हो गया। सहनी बैठक से निकले और तेजस्वी पर पीठ में चाकू घोंपने का आरोप लगाकर अंततः महागठबंधन से ही बाहर हो गए। एनडीए उनके बाहर होने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। सहनी की पार्टी को एनडीए में शामिल करा लिया गया। विधानसभा की ग्यारह सीटें दे दी। सहनी की पार्टी इस समय महागठबंधन में है। सहनी बता रहे हैं कि तेजस्वी के साथ उनका पक्का करार हो चुका है। इस बार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी सीएम बनेंगे। उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने का भरोसा दिया है। करार और वचन के बावजूद दावे के साथ यह कहना जोखिमों से भरा हो सकता है कि कम सीट मिलने के बाद भी सहनी महागठबंधन में ही बने रहेंगे। खैर, वह रह भी जाएं तो महागठबंधन में सीटों के लिए अंतिम समय में होने वाले किसी अप्रिय दृश्य की आशंका से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। कहिए तो महागठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती बने हुई है। महागठबंधन अगर सीटों का विवाद सहजता से सुलझा लेता है तो चुनाव से पहले ही उसकी यह बड़ी सफलता होगी।

नीतीश कुमार : प्रगति यात्रा के माध्यम से जनसमस्याओं पर नजर। फाइल

इस मोर्चे पर भी एनडीए आगे चल रहा है। इसके दो बड़े घटक दलों- भाजपा और जदयू के बीच सीटों को लेकर आंतरिक सहमति बन चुकी है। अंदरूनी तौर पर दोनों दलों को बता दिया गया है कि उसके हिस्से की सीटें कौन-कौन हैं? अन्य तीन घटक दल लोजपा (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को फिलहाल सीटों की संख्या के बारे में संकेत दे दिया गया है। मोटे तौर पर तय यह हो रहा है कि भाजपा-जदयू के बीच सौ-सौ सीटों का बंटवारा होगा। एकाध सीटें जदयू को अधिक दी जा सकती है। बची हुई 43 सीटों का बंटवारा तीन घटक दलों के बीच होगा। बेशक इसमें लोजपा (रा) को बड़ा हिस्सा मिलेगा। उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बारी आएगी। सीटों की संख्या के हिसाब से एनडीए के दलों का क्रम कुछ इस तरह हो सकता है- जदयू, भाजपा, लोजपा (रा), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा।

चुनाव की तैयारी में जुटे दोनों गठबंधनों के लिए अच्छी स्थिति यह है कि उनके बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना बन रही है। कम से कम आज की तिथि में कोई राजनीतिक दल या दोनों गठबंधनों से इतर छोटे दलों का ऐसा कोई संशय नजर नहीं आ रहा है, जो तीसरे मोर्चे की तरह चुनाव में सक्रिय रह कर दोनों बड़े गठबंधन को तनाव में डाल दे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आप की आवाज के आरसीपी सिंह ने पार्टी का गठन तो विकल्प देने के उद्देश्य से किया है, लेकिन जनता के बड़े हिस्से में इनकी पैठ अभी नहीं बन पाई है। कम समय में इनकी पैठ बन जाएगी, यह कहना मुश्किल है। अभी तो दोनों इस आशेष का भी ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर किस बड़े गठबंधन ने उन्हें बी टीम के रूप में नामित किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन अगर परवान चढ़ता तो प्रशांत किशोर को उसका लाभ मिल सकता था। लेकिन अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिलने के कारण यह पीके के लिए लाभकारी साबित नहीं हो पाया। आमरण अनशन के दौरान गिरफ्तार और रिहा हुए पीके इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। वे दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कुशल रणनीतिकार रहे हैं। इसलिए उनके लोग उनसे चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। चमत्कार जैसा कुछ हुआ तो अलग बात है, नहीं तो सामान्य परिस्थिति में तीसरे मोर्चे की जगह नहीं बन पा रही है।

मंथन

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता

अजय प्रताप तिवारी
सामाजिक अध्येता

पिछले कुछ समय से कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सुर्खियों में है। लिहाजा परीक्षा में पारदर्शिता कायम रखने के लिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए

हाल के दिनों में कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में हुए बदलाव से यह प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हुई है। परीक्षा को लेकर छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों के बदलाव का कोई प्रविधान नहीं है, फिर भी परीक्षा आयोग ने बदलाव किए थे। हालांकि आयोग ने छात्रों की समस्याओं को समझने के बाद अपने निर्णय को वापस लिया भी है, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई हैं। एक तय समयसीमा में पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का दबाव, नकल विहीन परीक्षा कराने की समस्या आयोग के लिए सिर दर्द बना हुआ है।

वहीं दूसरी ओर अधिकांश राज्यों में पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है। हर छोटी-बड़ी परीक्षाओं का प्रश्नपत्र लीक हो ही जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में पेपर लीक का मामला जोरों पर है। हाल में संपन्न बिहार राज्य लोक सेवा की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। कुल मिलाकर पेपर लीक का मामला गंभीर बन चुका है। इतना ही नहीं, परीक्षा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं द्वारा गलत प्रश्नपत्र बनाए जाने के कारण और भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव करने तथा कई अन्य कारणों से कई बार भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती है, जिससे छात्र पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। आखिर पेपर लीक, किसी प्रश्न का गलत होना, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव, प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भरने जैसी समस्याओं का निदान आयोग एवं सरकार क्यों नहीं पर पा रही है?

वस्तुतः किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होने से छात्रों पर उसका मानसिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से छात्र अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। पेपर लीक की घटनाएं न केवल भ्रष्टाचार का बढ़ता रूप है, बल्कि यह एक प्रशासनिक विफलता भी है। पेपर लीक प्रक्रिया अधिकारियों, कर्मचारियों और परीक्षा एजेंसियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। पेपर लीक होने के कई अन्य कारण भी हैं जिसमें पेपर छपने और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी का अभाव पेपर लीक का मुख्य कारण बनता है, कई बार परीक्षा प्रक्रिया में शामिल कुछ असंतुष्ट कर्मचारी जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं। प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण में पर्याप्त सुरक्षा का अभाव, परीक्षा फार्म और परीक्षा की तिथि निर्धारित न होना, सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ती प्रतिस्पर्धा, देश में बढ़ती बेरोजगारी पेपर लीक का कारण है।

पेपर लीक होने से केवल देश की शिक्षा व्यवस्था को साख पर सवाल नहीं खड़ा होता है, बल्कि छात्रों के भविष्य और देश की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकारों को सभी परीक्षा आयोगों का मूल्यांकन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विवादों के निराकरण हेतु अलग से एक राज्य परीक्षा नियंत्रण कोर्ट का गठन करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से कम से कम छह माह पहले परीक्षा आयोगों को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए तथा तीन सदस्यीय समिति गठित करके आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों के सुझाव को शामिल करने के बाद कोई बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में भर्ती प्रक्रिया बाधित न हो।

योग्य अभ्यर्थी के चयन के लिए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता का होना आवश्यक है। फाइल

उपाय : परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए आयोग को परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों के डिजी लाकर प्रोफाइल की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें परीक्षा के सभी चरणों की कापी को अपडेट करना चाहिए, ताकि सभी उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकें। इससे आयोग की खोई हुई विश्वसनीयता लौटेगी और छात्रों का संशय खत्म होगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा गलत प्रश्न बनाने पर दंड का प्रविधान किया जाना चाहिए। परीक्षा सेंटर पर सामूहिक नकल अथवा पेपर लीक होने पर संबंधित सेंटर पर दस साल कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। आनलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों की फेसस्कैनिंग और ओएमआर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्रश्नपत्र का मुद्रण सरकार और आयोग की निगरानी में सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। परीक्षा पेपर की सुरक्षा के लिए डिजिटल बाक्स की विशेष प्रणाली की व्यवस्था किया जाना चाहिए। परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन, ईमेल, वाट्सअप आदि पर परीक्षा से कुछ समय पहले से सरकारी एजेंसियों द्वारा नजर रखी जानी चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी परीक्षा योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए कराई जाती है, इसलिए परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

भारत-अफगान वार्ता

व्यावहारिक दृष्टिकोण

तालिबान को मान्यता न देने से लेकर भारत-अफगान वार्ता तक भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन व्यावहारिक है। भारत और तालिबान नीत अफगान सरकार के बीच दुबई में उच्चस्तरीय बैठक संबंध सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस संवाद में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री तथा अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री मवलावी आमिर खान मुत्ताकी ने भाग लिया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंध सुधारने तथा क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। इन वार्ताओं में आर्थिक, मानवीय व रणनीतिक सहयोग पर ध्यान दिया गया। इससे 2021 में तालिबान के सत्ता में वापसी से पैदा जटिल राजनीतिक स्थिति के बावजूद उससे संवाद का भारत का व्यवहारिक दृष्टिकोण रेखांकित होता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से जीवन्त तथा सांस्कृतिक व आर्थिक सहयोग से परिभाषित रहे हैं। लेकिन तालिबान की सत्ता में वापसी से द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हुए, हालांकि भारत ने मानवीय सहायता प्रदान कर सचेतन दृष्टिकोण बनाए रखा। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्रवाइयों तथा अफानिस्तान में व्याप्त भयावह मानवीय संकट ने संबंधों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता उजागर की है। ये चर्चायें क्षेत्रीय तनावों व खासकर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाईहमलों को देखते हुए प्रासंगिक हो जाती हैं जिनकी नई दिल्ली ने कठोर निन्दा की है। इस्लामाबाद की अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों के बीच इस साझा सरोकार ने भारतीय और अफगान हितों को एकसाथ ला दिया है तथा परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया है।

दुबई बैठक में व्यापक विषयों पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान की बहाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। उसने स्वास्थ्यरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा आपदा राहत में समर्थन जारी रखने तथा पहले से जारी योगदान, जैसे 50,000 मीट्रिक टन गेंहूं, चिकित्सा सप्लाई व वैक्सीनें बढ़ाने की बात कही।

इसके साथ ही दोनों पक्षों ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया जो व्यापार और मानवीय सप्लाई का प्रमुख रास्ता है। यह बंदरगाह पाकिस्तान को किनारे छोड़ कर अफगानिस्तान की विश्व बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करता है और युद्धग्रस्त देश की आर्थिक जीवनरेखा को स्थिर बनाता है। भारत ने विकास गतिविधियां बहाल करने की इच्छा प्रकट की जिसमें ढांचागत निर्माण तथा क्षमता-निर्माण परियोजनायें शामिल हैं। इससे संकेत मिलता है कि तालिबान प्रशासन की चुनौतियों के बावजूद भारत अफगानिस्तान के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में योगदान का इच्छुक है। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद तथा क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत के सरोकारों को संबोधित करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। उसने कहा कि अफगानिस्तान भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित स्वर्ग नहीं बनेगा। ये वार्तायें भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत हैं। इससे अन्य देश भी समान दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित हो सकते हैं और वे भी अफगान सरकार से संबंध बनाने की आवश्यकता को पहचान सकते हैं। लेकिन इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तव में इस क्षेत्र में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ने से रोकने के लिए भारत-अफगानिस्तान संबंध मजबूत करना है। काबुल के साथ इस्लामाबाद के रिश्तों में तनाव हालिया हवाईहमलों के बाद और बढ़ गया है। यह नई दिल्ली को एक अवसर प्रदान करता है कि वह एक विश्वसनीय साझेदार की भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ सके। चाबहार बंदरगाह से व्यापार और विकास परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने व गति देने से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। इससे मध्य एशिया में भारत को रणनीतिक महत्व भी मिलेगा।

ट्रंप सरकार से भारत के संबंध

ट्रंप द्वारा चीन से मुकाबले पर ध्यान केन्द्रित करने से भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध मजबूत हो सकते हैं, पर उनके आक्रामक व्यवहार से चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं।

भोपिंदर सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं)

डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों के प्रति भयावह तरीके से अपनी संप्रभु, गठबंधन व व्यक्तिगत जिम्मेदारियां छोड़ने की क्षमता प्रदर्शित की है। वे महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक जिम्मेदारियों से भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी जल्दी से छोड़ सकते हैं जिसके उदाहरण अफगानिस्तान तथा वर्तमान समय में सीरिया हैं। वे बिना सोचे-विचारे अपने कंधे झटक कर कह सकते हैं कि 'यह हमारी समस्या नहीं' है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न देशों के साथ उनके संबंध प्रभावित होंगे क्योंकि कोई भी ट्रंप से किसी सहायता की उम्मीद नहीं करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से भारत में उत्तेजना, आशंका तथा चिन्ता का भी माहौल है। जहां ट्रंप के आक्रामक व्यवहार से सभी परिचित हैं, वहीं अपने पिछले अनुभव के आधार पर वे बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। हालांकि, भारत उनकी विदेश नीति में अत्यधिक प्रासांगिक और महत्वपूर्ण है, पर भारतीय प्रतिक्रिया और व्यवहार की परीक्षा के लिए कुछ मुद्दों से निपटना जरूरी होगा। वे चीन के प्रबंधन पर अत्यधिक केन्द्रित हैं और उससे मुकाबला करने के लिए भारत रणनीतिक 'धुरी' सिद्ध होगा। हालांकि, रूस और ईरान जैसे देशों के साथ नई दिल्ली के गहरे समीकरण उनको उत्तेजित और गुस्सा कर सकते हैं। ऐसे में काफी कुछ 'टीम ट्रंप' पर निर्भर करेगा जो 'मागा', यानी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के चुनावी वादे को पूरा करने में उनकी सहायता करेगी। लेकिन पहले कार्यकाल के उलट, जब उन्होंने ट्रंप प्रशासन में सम्मानजनक व पेशेवर लोगों की विरासत प्राप्त की थी, इस बार वे केवल ट्रंप के प्रति व्यक्तिगत 'निष्ठा' पर आधारित होंगे, हालांकि बाद में उन्होंने अपने अनेक सहयोगियों के लिए 'रिवाल्विंग डोर' जैसी नीति अपना ली थी। हाल की अनेक नियुक्तियों को देखते हुए यह चिन्ता और सरोकार पैदा होते हैं कि क्या मामला 'पहले की तरह' ही चलता रहेगा, जिसकी दिल्ली की आदत थी और वाशिंगटन में सरकार बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुःख की बात है कि इस बार ट्रंप के पहले प्रशासन की तरह परिपक्व लोग टीम में शामिल नहीं होंगे जो ट्रंप को उनकी बचकानी और आक्रामक हरकतों से रोकने और सही दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। इस बार उनके साथ 'निष्ठावान' लोगों की भीड़ होगी जो ट्रंप के विचारों को और हवा देने में प्रतियोगिता करने लगेंगे, भले ही वे चाहे जैसे हों। ऐसे में देखना होगा कि चीन की चिन्ता करने वाले भारत, जापान या आस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रति ट्रंप की 'अ-हस्तक्षेपकारी' नीतियां क्या दिशा लेंगी, जबकि वे तीनों देश क्वाड का हिस्सा हैं। इसी कारण वे देश चीनी आक्रामकता और विस्तारवाद का सीधे मुकाबला करते हैं। क्या ट्रंप की अ-हस्तक्षेपकारी नीति से बीजिंग का दुःसाहस बढ़ जाएगा और वह ताइवान पर यह समझ कर हमला कर देगा कि बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद वाशिंगटन इसमें सैनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा? आंशिक रूप से अलग-थलग व पीड़ित यूक्रेन से उभरने वाली तस्वीर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आश्वस्त नहीं करती है। ऐसे में अमेरिका द्वारा अपने 'सहयोगियों' पर दबाव डालने की संभावना दिखती है। उल्लेखनीय है कि 2020 की गर्मियों में जब चीनी आक्रामकता भारतीय सीमाओं पर दबाव डाल रही थी तब ट्रंप ने ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने के बजाय दोनों की बीच 'वार्ता कराने' का प्रस्ताव किया था।

हालांकि, अमेरिकनों ने दिल्ली को हथियारों का निर्यात बढ़ा दिया था, पर यह सब ट्रंप जैसे कट्टर बिजनेसमैन के लिए वाणिज्यिक हित का मामला अधिक था। ऐसे में भविष्य में ऐसी किसी आपातस्थिति से निपटने में ट्रंप के समर्थन का क्या अर्थ हो सकता है। इस समर्थन की विफलता पर गंभीरता से विचार की आवश्यकता है। द्विपक्षीय संबंधों में भी ट्रंप कैबिनेट के कारण तनावों की संभावना पैदा हो सकती है। ऐसे में राजनय के परंपरागत नियम लागू हो सकते हैं या नहीं? संभावना है कि भारतीय सब्सिडी के प्रति कुछ असहज करने वाली टिप्पणियां भी सामने आ सकती हैं। ऐसे में दिल्ली के समक्ष द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले भारी दबाव को हल्का करने तथा विचार-विमर्श जारी रखने का दबाव बना रहेगा। भारतीय लोकतंत्र की अपनी गतिशीलता है और उसका दृष्टिकोण असहज करने वाली टिप्पणियां अस्वीकार करना है, फिर चाहे वह अमेरिका की ओर से ही क्यों न आ रही हों। इस बात से जटिलता और विरोधाभास बढ़ सकते हैं कि ट्रंप की नई कैबिनेट में अनेक लोग आक्रामक-हस्तक्षेपकारी हैं। इनमें विदेश सचिव मार्को रूबियो, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत इलिशी स्टेफिंक, आदि शामिल हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इन कट्टरपंथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

यही तक कि आप्रवास, व्यापार की शर्तों या पर्यावरण मुद्दों पर प्रतिबद्धता जैसे 'गैर-सुरक्षा' मुद्दों पर नई दिल्ली को नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण बहुपक्षीय मंचों पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतायें प्रकट की हैं, जबकि ट्रंप इस मुद्दे पर केवल लफ्फाजी भरी बातें ही करते रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण संकट तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी चिन्ताओं को खारिज करते हुए यहां तक कह दिया था कि 'मैं इस हरित घोटाले को खारिज कर दूंगा।' हालांकि, आप्रवास संबंधी मुद्दे में भारत सर्वोच्च स्थान पर नहीं है, पर समय बीतने के बाद ही पता चलेगा कि 'भारतीय हमारे रोजगार छीन रहे हैं' जैसे बयानों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप एक अत्यधिक लोकरंजक नेता हैं जो अपनी इच्छाओं को किसी सीमा तक भी आगे बढ़ाना चाहेंगे, ऐसे में देखना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंध कैसे रहेंगे। दूसरे देशों से संबंधों की तुलना में इसका महत्व अधिक होगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों के प्रति भयावह तरीके से अपनी संप्रभु, गठबंधन व व्यक्तिगत जिम्मेदारियां छोड़ने की क्षमता प्रदर्शित की है। वे महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक जिम्मेदारियों से भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी जल्दी से छोड़ सकते हैं जिसके उदाहरण अफगानिस्तान तथा वर्तमान समय में सीरिया हैं। वे बिना सोचे-विचारे अपने कंधे झटक कर कह सकते हैं कि 'यह हमारी समस्या नहीं' है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न देशों के साथ उनके संबंध प्रभावित होंगे क्योंकि कोई भी ट्रंप से किसी सहायता की उम्मीद नहीं करेगा। पहचान की ध्रुवीकरण वाली राजनीति तथा बेंजामिन नेतनयाहू जैसे लोगों का आंख बंद कर समर्थन करने के कारण व्हाइट हाउस से निकलने वाला संदेश भारत जैसे विविधतापूर्ण तथा समावेशी दृष्टिकोण अपनाने वाले देशों के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा मैक्सिको के साथ सीमायें बंद करने तथा अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अवैध आप्रवासी निष्कासन अभियान के वादे के कारण अमेरिका में भी उथलपुथल वाली स्थिति पैदा हो सकती है। ये वादे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में विजय के बाद कुछ ही घंटों के भीतर किए हैं। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादातर लफ्फाजी करनी के बजाय कथनी होती है, पर भारत को एक सीमा के बाद उनकी उकसावे भरी बातों तथा अराजक व्यवहार से परेशानी हो सकती है।

ट्रंप की वापसी और आसियान देश

ट्रंप की वापसी से दक्षिणपूर्व एशिया स्वयं को अमेरिकी दुविधा के एक और युग के लिए तैयार कर रहा है।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं।)

अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से दक्षिणपूर्व एशिया अमेरिकी विदेश नीति में अनिश्चितता के एक और युग के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। ट्रंप की विजय के बाद औपचारिक धन्यवाद देते हुए दक्षिणपूर्वी एशियाई देश अब इस दुविधा का शिकार हैं कि उनके प्रशासन का अर्थव्यवस्थाओं तथा रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र की सरकारें राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के उलट एकदम अलग प्रशासन के लिए तैयार हो रही हैं जिनमें व्यापार संबंधों, राजनयिक संबंधों तथा क्षेत्रीय स्थिरता में नाटकीय परिवर्तन शामिल हैं। असोसियेशन आफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स-आसियान के दस सदस्य देश इंडोनेशिया से म्यांमार तक फैले हैं। ये जानते हैं कि दक्षिणपूर्ण एशिया शायद नए प्रशासन की प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान पर न हो। ट्रंप अपनी अनुमान से परे राजनयिक शैली के लिए जाने जाते हैं। आसियान देश ट्रंप प्रशासन की अस्थिरता को समझते हुए सावधानी से आशावादी है कि उनकी वापसी से गंभीर व्यापार वार्तायें शुरू हो सकती हैं। अनेक क्षेत्रीय नेताओं का विश्वास है कि ट्रंप द्वारा प्रत्यक्ष व द्विपक्षीय वार्ताओं की पसंद को देखते हुए खास देशों को ज्यादा लाभदायक समझौतों का अवसर मिल सकता है। इनमें बहुपक्षीय समझौतों से खासकर अलग रहने वाले देश शामिल हैं। लेकिन दक्षिणपूर्व एशिया में अधिकांश गंभीर समस्यायें अमेरिका-चीन संबंधों पर केन्द्रित हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में आसियान देशों को चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाना पड़ा था क्योंकि वे दूसरे देश को गुस्सा किए बिना अपनी आर्थिक वृद्धि व क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। महामारी-पश्चात युग में यह स्थिति काफी बदल गई थी क्योंकि चीन और आसियान एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापार साझीदार के रूप में उभरे थे। अमेरिका-चीन

संबंधों की दिशा का दक्षिणपूर्व एशिया के आर्थिक स्थायित्व व सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन में ये संबंध तनावपूर्ण थे जिनमें व्यापार युद्ध व सैनिक तनाव शामिल था। कट्टर चीन-आलोचक मार्को रूबियो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से यह संकेत मिला है कि अमेरिका चीन से टकराव जारी रखेगा जिससे क्षेत्रीय राजनीति बाधित हो सकती है। जहां अनेक आसियान देशों के नेताओं को कट्टरपंथी अमेरिका-चीन राजनीति से चिन्ता है, वहीं बस बात की उम्मीद भी है कि ट्रंप के प्रशासन में दक्षिणपूर्व एशिया के बहुप्रतीक्षित व्यापार और रणनीतिक महत्व पर ध्यान दिया जाएगा। इससे संसाधनों से समृद्ध इंडोनेशिया व फिलीपीन्स जैसे देशों को लाभ हो सकता है जो एलेक्ट्रानिक्स व हरित तकनीकों में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। दूसरी ओर आसियान देशों को चिन्ता है कि उनको अमेरिका द्वारा व्यापार घाटा कम करने के प्रयासों का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।

इन अनिश्चितताओं के बावजूद आसियान देशों का प्रमुख लक्ष्य स्थायित्व एवं संतुलन बना रहेगा। आसियान देश दोनों वैश्विक शक्तियों के साथ स्थिर संबंधों पर जोर देते रहेंगे और उनका उद्देश्य स्वयं को अमेरिका-चीन तनावों के सबसे बुरे प्रभावों से सुरक्षित रखना होगा। इसके साथ ही वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक स्पेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भारत इस स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहा है ताकि वह पीछे न छूटने पाए। भारत अच्छी तरह जानता है कि जल्द ही ट्रंप दिलली पर निशाना लगाएंगे। दिल्ली आसियान समूह के कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के प्रयास कर रहा है, हालांकि वह पूरी शक्ति के साथ बहुपक्षीय प्लेटफार्म पर सहभागिता भी कर रहा है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया गणतंत्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे जो आसियान समूह का एक प्रमुख देश है। अमेरिका को भारत का निर्यात ट्रंप की कट्टरपंथी नीति के कारण प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उसे अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की आवश्यकता होगी तथा सावधानी से अपने घरेलू कानूनों और व्यापार बाधाओं को सहज बनाना होगा। अमेरिका के साथ इस क्षेत्र के भावी संबंध न केवल ट्रंप के घरेलू एजेंडे, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि आसियान और भारत अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों में नाजुक संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। आने वाले वर्षों में उनको अमेरिकन और चीनी प्रभावों के बीच संतुलन बनाना होगा।

आप की बात

इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पॉलिसी तैयार करने की खबर स्वागत योग्य है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ाया गया है। हाल के दिनों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने और उससे जनधन हानि होने के समाचार आए थे। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुरक्षा के लिए कड़े मानक तैयार करने होंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माताओं को भी अपने उत्पादों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रदूषण बचाने के कार्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल महत्वपूर्ण है और जनता में भी नौकरी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही पॉलिसी में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए। पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुरक्षा के लिए कड़े मानक तैयार किए जाने चाहिए। पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माताओं को अपने उत्पादों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पॉलिसी में उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। पॉलिसी में दुर्घटना की स्थिति में कार्रवाई के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

-**सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

ई-कॉमर्स बनाम पारंपरिक दुकानें

भारत में पारंपरिक किराना दुकानें समाज की रीढ़ मानी जाती रही हैं। ये दुकानें न केवल रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं, बल्कि स्थानीय समुदायों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी भी थीं। ग्राहकों और दुकानदारों के बीच बने आत्मीय संबंध इनका विशेष पहलू थे। लेकिन, डिजिटल युग की तेज़ी, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की बढ़ती लोकप्रियता और बड़े रिटेल चेन के उभार ने पारंपरिक दुकानों के अस्तित्व को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। 2015 से 2023 के बीच किराना दुकानों की संख्या में 15-20% की गिरावट दर्ज की गई है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बिगबास्केट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को उनकी सुविधा के अनुसार उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह बदलाव अधिक स्पष्ट है, परंतु इसकी छाया अब ग्रामीण इलाकों में भी पड़ने लगी है। ई-कॉमर्स और बड़े रिटेल चेन के साथ प्रतिस्पर्धा, महंगाई, थोक कीमतों में बढ़ोतरी, और डिजिटल तकनीक की कमी छोटे दुकानदारों के लिए मुख्य चुनौतियाँ हैं। समाधान के लिए छोटे दुकानदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मार्केटिंग के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना आवश्यक है। सरकार को भी विशेष योजनाओं और सस्ती ऋण योजनाओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। पारंपरिक दुकानों का अस्तित्व केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक महत्व भी रखता है।

-**प्रो. आरके जैन अरिजीत**, बड़वानी

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

रतलाम का एक समाचार दिल दहला गया कि जिसमें एक बैटरी से चलने वाली गाड़ी में उसे चार्ज करते समय उसमें विस्फोट हो गया तथा एक बच्ची के मृत होने एवं कुछ लोगों के घायल होने का समाचार पढ़ा। तब इस प्रकार बैट्री से चलने वाले वाहनों के प्रति मन में काफी शंका भर गई। कारण इन दिनों जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तब उससे तो यही लगता है कि यह एक सहूलित वाली गाड़ी है परंतु जिस तरह से इसमें चार्ज करते समय विस्फोट हुआ तब इन वाहनों के प्रति मन में काफी डर भी बैठ गया। कारण इन्हें कितने समय तक लगातार चार्ज करना है इसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई रात के समय इसे चार्ज कर रहा है उसको चार्जिंग समय ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, वरना लगता तो यही है कि इसे लगातार चार्ज पर लगाकर असावधानी बरतना तो मौत को दावत देना है। अतः इसके चार्ज करने के घंटे दिमाग में रखकर चार्ज करना बेहद जरूरी है वरना सावधानी हटी के दुर्घटना घटी। फिर हमें तो यही चाहते हैं कि इसके पूर्ण चार्ज होने पर इसमें अलार्म बजने का सिस्टम लगाना बेहद जरूरी है ताकि समय पर इसका बटन बंद किया जा सके। जिस तरह उपर पानी की टंकी में पानी भरने पर वहां अलार्म से सूचना मिलती है कि पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दें इसी तरह का सिस्टम यहां भी जरूरी है।

-**एमएम राजावत राज**, शाजापुर

अप्रिय घटना

तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में वैकुंठद्वार दर्शन टिकट काउंटर पर टोकन वितरण के समय भगदड़ मच गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। काउंटर के पास 4,000 से अधिक श्रद्धालु लाइन में खड़े थे। जैसे ही श्रद्धालुओं को बैरागी पट्टा पार्क में कतार लगाने को कहा गया, सभी पहले स्थान पाने की होड़ में जुट गए, जिससे भगदड़ मच गई। इस अफरातफरी में श्रद्धालु एक-दूसरे पर गिरने लगे और चारों ओर हड़कंप मच गया। भारी भीड़ के बीच कई लोगों का दम घुटने लगा। तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी अनुशासित व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ देने और एक ही समय में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रबंधों के कारण इसे एक आदर्श मंदिर प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस घटना के दौरान अचानक भीड़ प्रबंधन में विफलता चिंता का विषय है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने 1.2 लाख मुफ्त टिकट बांटने की घोषणा की थी -**दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई**

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

कल्पमेधा

स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी आश्रय पर नहीं जीवित रहते हैं। वे सहारा अवश्य मांगते हैं, पर अपमानित कभी नहीं होना चाहते, यही उनकी विशेषता है।

- टोरी

दोस्ती का हाथ

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों में दूरी आ गई है। मगर अब अफगानिस्तान ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वहां के कार्यवाहक विदेशमंत्री ने मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार जताते हुए कहा कि वे अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति के अनुरूप राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने अपील की कि भारत व्यापारियों, रोगियों और विद्यार्थियों के लिए वीजा जारी करना शुरू करे। उनकी अपील पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते फिर से मजबूत हों। उसके साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ें और परियोजनाओं पर काम शुरू हो। मगर चूंकि वहां तालिबान के सत्ता में आने के बाद दुनिया के अनेक देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और तालिबान के सत्ता हथियाने के तरीके को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया, इसलिए भारत ने भी स्वाभाविक ही उससे दूरी बना ली। हालांकि जरूरत के वक्त भारत उसे मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है। मगर अफगानी छात्रों के लिए वीजा जारी करने संबंधी फैसले को लेकर काफी समय से मंथन चल रहा है। इसलिए इस पर भारत के लिए विचार करना मुश्किल नहीं है। दरअसल, वीजा न मिल पाने के कारण भारत में पढ़ रहे बड़ी संख्या में अफगानी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

अफगानिस्तान व्यापारिक रूप से भारत का एक बड़ा सहयोगी पड़ोसी रहा है। भारतीय कंपनियां वहां की विकास परियोजनाओं में लगी रही हैं। इस तरह, तालिबान के सत्ता में आने के बाद बनी दूरी से दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुनिया के कई देश अपने रणनीतिक लाभ के लिए अफगानिस्तान के साथ रिश्ते फिर से बहाल कर लिए हैं। ऐसे में, भारत के लिए बहुत देर तक दूरी बनाए रखना भी ठीक नहीं समझा जा रहा। सार्क समूह के विखंडित होने के बाद उपजी स्थितियों का लाभ चीन उठाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भी अफगानिस्तान से भारत की नजदीकी रणनीतिक दृष्टि से जरूरी है। अफगानिस्तान भारत के लिए एक बड़ा बाजार है, इसलिए आर्थिक रणनीति के तहत उसे खोना नहीं चाहिए। यही वजह है कि भारत ने कहा है कि वह अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बहाल और मजबूत करने पर विचार कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को अफगानिस्तान से काफी कारोबार मिलता है। हर वर्ष करीब तेरह हजार विद्यार्थी वहां से आते हैं। इसी तरह बहुत सारे रोगी यहां के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं।

भारत वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है। साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन संबंधी योजनाओं को प्रश्रय देता है। अफगानिस्तान से आने वाले विद्यार्थियों और रोगियों को रोकना उसके लिए फायदेमंद नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि तालिबान के कई फैसले और नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं कही जा सकतीं। मगर फिलहाल वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के आसार नजर नहीं आ रहे, तो इसी बीच कोई सकारात्मक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जो अफगानी छात्र 2021 से वीजा न मिलने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, उनके भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वे बार-बार मांग करते रहे हैं कि उन्हें वीजा जारी किया जाए। अफगानी विदेशमंत्री की अपील पर भारत सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है, जो रणनीतिक रूप से एक अच्छा संकेत है।

बेटियों का हक

हालांकि एक सभ्य समाज में बेटे और बेटी के अधिकारों में अंतर का सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन कई वजहों से जड़ जमा चुके पूर्वाग्रहों की वजह से आमतौर पर बेटियों को कई स्तर पर समझौता करना पड़ता है। ऐसी स्थिति की मुख्य वजह पारंपरिक धारणाओं के प्रति ज्यादातर लोगों की सहजता होती है, जिसमें बेटियां अपने हक के प्रति उदासीन रहती हैं या फिर वंचित रह जाती हैं। फिर किन्हीं कारणों से माता-पिता के अलग हो जाने की स्थिति में भी बेटी की पढ़ाई-लिखाई सिर्फ खर्च पूरा नहीं हो पाने की वजह से बाधित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के बाद इसी मसले पर एक तरह से स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने छब्बीस वर्ष से अलग रह रहे दंपति के मामले में कहा कि बेटियों को अपने अभिभावकों से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर माता-पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की पढ़ाई-लिखाई के लिए जरूरी धन दें। बेटी को ये पैसे रखने का अधिकार है और यह रकम उसे अपनी मां या पिता को लौटाने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, ऐसे मामले अक्सर देखे जाते रहे हैं जिनमें परिवारों में अगर संपत्ति के बंटवारे की स्थिति आती है तो जितने हिस्से पर बेटों का सहज हक माना जाता है, उतने के लिए बेटियों को अलग से प्रयास करना पड़ता है। विडंबना यह है कि अगर किसी परिवार में माता-पिता को शिक्षा पर खर्च के मामले में बेटी या बेटे में से किसी एक को ही चुनने का विकल्प हो तो वे आमतौर पर बेटे को प्राथमिकता देते हैं। अगर कभी बेटी को उनका हिस्सा दिया जाता है तो उसे समाज में विशेष रूप से दी गई सुविधा की दृष्टि से देखा जाता है। जबकि सामाजिक बराबरी के सिद्धांत से लेकर कानूनी स्थिति तक के लिहाज से बेटियों को उनके माता-पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होना चाहिए और इसे लेकर लोगों को सहज रहना चाहिए। खासतौर पर पालन-पोषण और पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ अन्य जरूरी खर्च के मामले में माता-पिता की आर्थिक सीमा में बेटियों को उनसे अपना खर्च लेने का अधिकार होना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो बेटियों के हक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला स्वागतयोग्य है।

बढ़ते मरुस्थल से घटते संसाधन

सूखे के साथ ही मरुस्थल बढ़ने के कारण वैश्विक मानचित्र तेजी से बदल रहा है। हर साल दस करोड़ हेक्टेयर यानी मिस्र देश के आकार के बराबर की उत्पादक भूमि सूखा और मरुस्थल की भेंट चढ़ती जा रही है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

पृथ्वी को मरुस्थलीकरण से बचाने और भोजन, कपड़ा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए उत्पादक भूमि की रक्षा करना जरूरी है। विश्व की 3.20 अरब आबादी इस समय विस्थापन का संताप झेल रही है। स्थानीय स्थितियां लोगों को प्रवास के लिए विवश कर रही हैं। मिट्टी अपनी उत्पादकता खोती जा रही है। भू-प्रबंधन की व्यवस्था असुरक्षित हो रही है। भूमि-आधारित रोजगारों का समाधान ढूंढ़ पाना कठिन हो रहा है। तेजी से वनों की कटाई मरुस्थलों का विस्तार कर रही है। इस समय दुनिया में मात्र 60 फीसद जंगल बचे हैं। मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि पुनर्बहाली पर वैश्विक विमर्श हो रहे हैं। विश्व की 40 फीसद भूमि क्षरित हो चुकी है, यानी इसकी जैविक उत्पादकता लगातार ह्रास की ओर है। इसका जलवायु, जैव विविधता और लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि भूमि-क्षरण से सूखा, रेत और धूल भरे तूफानों से जन-जीवन दूभर हो रहा है। भू-वेत्ता और मौसम विज्ञानी आगाह कर रहे हैं कि आगामी दो दशक बाद दुनिया में भयावह सूखे के कारण तीन चौथाई आबादी को पेयजल संकट से दो-चार होना पड़ सकता है।

सूखे के साथ ही मरुस्थल बढ़ने के कारण वैश्विक मानचित्र तेजी से बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह, जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन है। सूखे के जोखिमों की प्रणालीगत प्रकृति दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा, कृषि, नदी परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी एक दूसरे से जुड़ी स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। दुनिया भर में जन जीवन और आजीविका बचाने के लिए अब तो सूखे के प्रति सहन क्षमता बढ़ाने के लिए सत्तर से अधिक देशों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित डेटा मंच भी सक्रिय हो चुका है। सूखा सहन सक्षमता साझेदारी को वित्तपोषित करने के लिए 2.15 अरब डालर के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी हो चुकी है।

तीन दशक पहले दुनिया के 196 देशों और यूरोपीय संघ ने मरुस्थलों से निपटने के लिए एक साझा मसविदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसी पर आपसी विमर्श के लिए पिछले दिनों एक बैठक सऊदी अरब के रियाद में भी हुई थी। ताजा अध्ययनों से पता चलता है कि वर्ष 2000 के बाद से अब तक भूमि-क्षरण में 29 फीसद की बढ़ोतरी हो चुकी है। भूमि क्षरण से प्रभावित आबादी महंगाई, बेरोजगारी और अप्रत्याशित ऊर्जा बोझ से कराहने लगी है। भूमि और मिट्टी का नुकसान निर्धन परिवारों को पौष्टिक भोजन और बच्चों के सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रहा है।

इस दिशा में सबसे सशक्त और सार्थक पहल संयुक्त राष्ट्र की रही है। भूमि बचाने में विश्व की मौजूदा दुलमुल आर्थिकी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से धन जुटाने के प्रयासों को अब काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अनुमानित तौर पर इसके लिए संचयी निवेश वर्ष 2030 तक कुल 2.6 ट्रिलियन डालर जरूरी माना जा रहा है। नागरिक समाज संगठनों का कहना है, यह उतनी ही राशि है, जितनी दुनिया वर्ष 2023 में रक्षा बजट पर खर्च कर चुकी है। इस चुनौती से पार पाने के लिए अब सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं, युवाओं, चरवाहों और स्थानीय

समुदायों की सार्थक भागीदारी को संस्थागत बनाना जरूरी हो गया है। हर साल दस करोड़ हेक्टेयर यानी मिस्र के आकार के बराबर की उत्पादक भूमि सूखा और मरुस्थल की भेंट चढ़ती जा रही है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रहा सूखा ऐसा खामोश हत्यारा बन चुका है, जिससे बचना, ऐसे किसी भी प्रभावित देश के लिए असंभव-सा होता जा रहा है। इससे कृषि, जल सुरक्षा और 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। इसका सबसे बड़ा खमियाजा निर्धनतम देश भुगत रहे हैं। अंदेशा है कि निकट भविष्य में पानी जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच बड़े टकरावों का कारण बन सकती है। विस्थापन का संकट और अधिक भयावह हो सकता है। बीते तीन वर्षों से दुनिया के ऐसे 30 से अधिक देशों में सूखे के भयावह हालात हैं।

> **प** र्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रहा सूखा ऐसा खामोश हत्यारा बन चुका है, जिससे बचना, ऐसे किसी भी प्रभावित देश के लिए असंभव होता जा रहा है। इससे कृषि, जल सुरक्षा और 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। इसका सबसे बड़ा खमियाजा निर्धनतम देश भुगत रहे हैं। अंदेशा है कि निकट भविष्य में पानी जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच बड़े टकरावों का कारण बन सकती है। विस्थापन का संकट और अधिक भयावह हो सकता है। बीते तीन वर्षों से दुनिया के ऐसे 30 से अधिक देशों में सूखे के भयावह हालात हैं।

ऐसा खामोश हत्यारा बन चुका है, जिससे बचना, ऐसे किसी भी प्रभावित देश के लिए असंभव-सा होता जा रहा है। इससे कृषि, जल सुरक्षा और 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। इस सबसे बड़ा खमियाजा निर्धनतम देश भुगत रहे हैं। अंदेशा है कि नि भविष्य में पानी जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच टकरावों का कारण बन सकती है। विस्थापन का संकट और अ भयावह हो सकता है। बीते तीन वर्षों से दुनिया के ऐसे 30 से अ देशों में सूखे के भयावह हालात हैं। इस स्थिति से प्रभावित उत्तरी, द अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ ही भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा स्पेन जैसे देशों पर भी इसकी छाया पड़ चुकी है।

सूखे के कारण यूरोप की राइन नदी का अनाज परिवहन अमेरिका में पनामा व्यापार मार्ग बाधित हो चुका है। ब्राजील जलवि संकट से जूझ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लगातार सूखा के विस्तार से वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में लोग की चपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह वर्षा की कमी ही नहीं, जल परिवर्तन और भूमि कुप्रबंधन भी है। पहाड़ी वनों की कटाई से व्य भू-क्षरण हो रहा है। इससे सूखा ही नहीं, ताप लहर और बाढ़ जैसे आसन्न हैं। ऐसी स्थितियों में आजीविका का जोखिम कई गुना जाएगा। पारिस्थितिकी आपदा पूरे विश्व की सामाजिक और आ व्यवस्थाओं को झकझोर सकती है।

इस समय दुनिया भर में हरित मिशन चलाने वाले दस युवा ' नायक' भी मरुस्थलीकरण पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। से एक हैं गरीब किसान परिवार के हिमांशु सकोरे। वे मुख्यतः मिट्टी की रोकथाम पर काम करने के साथ जैविक कृषि वानिकी नवाचार महाराष्ट्र के किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हरित उद्यमी रोकियातु त्राओरे माली में मारिंगा पेड़ पर आधारित सामाजिक उद्यम चला रही हैं। अब तक उन्होंने कई महिलाओं को हजार मोरिंगा पेड़ों से जैविक चाय, पाउडर, तेल, साबुन, मसाले और आहार आदि बनाने में प्रशिक्षित किया है। जिम्बाब्वे के भूमि-न तकुदजवा एप्सले अपने संगठन 'फारेस्ट्री एंड स्ट्रस रिसर्च' के माध्य मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सैटेलाइट तक का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए दुनिया में स संवेदनशील देश फिलीपींस में 'मसुंगी जियोरिजर्व फाउंडेशन' के अ बिली क्रिस्टल जी डुमालियांग मनीला के आसपास लगभग 2, हेक्टेयर क्षतिग्रस्त जलग्रहण क्षेत्रों की पुनर्बहाली और पर्यावरणीय सं स्थापित करने में जुटे हुए हैं। इसी तरह एस्ट्रिड पेराजा कोस्टारिक जलवायु शिक्षक के रूप में एक बोर्ड गेम विकसित कर खिलाड़ियों जलवायु परिवर्तन और उसके समाधानों का पाठ पढ़ा रहे हैं।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने प्राकृ स्थिरता और जन जीवन की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दुनिया की सरकारों, निजी क्षेत्र की आर्थिक शक्तियों और समुदायों से क्षरण की रोकथाम और पृथ्वी की रक्षा की दिशा में पुरजोर कदम उ का आह्वान किया है। उनका कहना है कि हर सेकंड चार फुट मैदानों के आकार की उत्पादक भूमि, क्षरण की चपेट में आ रही बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में घटते उत्पादन और बढ़ती खपत के टिकाऊ तौर-तरीकों के कारण भी प्राकृतिक संसाधन सिकुड़ते जा हैं। ऐसे हालात में हर वर्ष विस्थापितों की संख्या बढ़ रही है।

चेहरे पर चेहरा

सुरेशचंद्र रोहरा

यह एक मशहूर कहावत है कि लिफाफे का मुखड़ा देखकर मजमून समझ में आ जाता है। बहुतेरे लोग तो किसी का मुख-मंडल देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं और वह सही भी होता है। दरअसल, इसके लिए अनुभव और दीर्घ दृष्टि की जरूरत होती है। चेहरा किसी का आत्मविश्वास, उसकी गंभीरता, नेतृत्व क्षमता, विश्वसनीयता, दृढ़ता और संकल्प के साथ-साथ एक प्रकार की संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई को भी अभिव्यक्त कर जाता है। यह चेहरा ही है जो व्यक्ति की विचारशीलता और उसके विचारों की गहराई को भी प्रकट करता है, जैसे कि व्यक्ति अपने शब्दों का चयन सावधानी से करता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करता है। चेहरा एक प्रकार की तैयारी और सावधानी को भी दर्शाता है, जैसे कि व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों के परिणामों के बारे में सोच रहा है। मुखड़ा हमारी पहचान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि चेहरा किसी के व्यक्तित्व, भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से प्रकट नहीं भी कर सकता है।

दरअसल, चेहरा एक आवरण भी है, जो हमारे अंदर की दुनिया को छिपाता है। हमने कई बार देखा है चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन अंदर दुख और दर्द भरा रहता है। चेहरे पर गंभीरता हो सकती है, लेकिन भीतर मजाक और हास्य हो सकता है। चेहरे पर आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन अंदर संदेह और भय हो सकता है। इसलिए चेहरे को देखकर किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी के शब्दों, कार्यों और व्यवहार को देखना चाहिए, ताकि हम उनके व्यक्तित्व और भावनाओं को बेहतर ढंग से अनुभूत कर सकें। एक पहलू यह भी है कि चेहरा देखकर धोखा खाना बहुत आसान हो सकता है। कुछ लोग अपने चेहरे पर एक आवरण ओढ़ लेते हैं जो उनके वास्तविक विचारों और भावनाओं को छिपा देता है।

चेहरा देखकर धोखा खाने से बचने के लिए चेहरे को गहराई से देखकर हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति के विचार और भावनाएं क्या हैं। सच यह है कि व्यवहार चेहरे से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। बातचीत कर भी हमें व्यक्ति के विचार और भावनाएं समझने में मदद मिल सकती है। पिछले अनुभवों को याद रखकर हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति कैसा है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति कैसा है।

चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति और भावनाएं व्यक्ति के दिल की सच्चाई को दर्शाती हैं। चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान, आंखों की चमक और भौहों की आकृति व्यक्ति के दिल की खुशी, दुख और भावनाओं को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति खुश होता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो उसके चेहरे पर उदासी और दुख की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इसलिए चेहरे को दिल का आईना कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति सदैव सच्ची नहीं होती हैं। यह एक प्रकार का प्रतीक हो सकता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने चेहरे पर एक और चेहरा बना सकते हैं! एक तरह से हम अपने चेहरे पर एक और चेहरा बना लेते हैं। अक्सर हम आवरण पहनते हैं या अपने चेहरे को सजाते हैं। मगर सवाल है कि क्या यह नया चेहरा हमारे असली चेहरे को छिपाता है या यह हमारे असली चेहरे का एक हिस्सा है! एक और तरीके से चेहरे पर चेहरा हमें अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।

दरअसल, चेहरा और विचार के बीच का संबंध एक जटिल विषय है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चेहरा और विचार एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रसंग में बच्चों के चेहरे पर एक प्रकार की मासूमियत, निर्दोष खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई देती है जो हमें भाव-विभोर करती है। मासूम बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और हम भी उनके साथ प्रसन्न होते हैं। बच्चों की आंखों और मुख पर एक निश्छल चमक और निर्दोष भाव अभिव्यक्त होता है जो हमें आकर्षित करता है। उनकी मुस्कान में एक प्रकार की खुशी और आनंद की अभिव्यक्ति होती है जो हमें भी खुशी से भर देती है। दूसरी ओर, किसी बुजुर्ग के चेहरे पर एक प्रकार का अनुभव, ज्ञान और जीवन की गहराई की अभिव्यक्ति होती है। बुजुर्गों के चेहरे पर वृद्धावस्था के चिह्न, जैसे कि झुर्रियां, गहरी लकीरें और सफेद बाल, उनकी उम्र और अनुभव को दर्शाती हैं। चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और वे खुश हैं या नहीं। बुजुर्गों की मुस्कान एक प्रकार की शांति और संतुष्टि की अभिव्यक्ति होती है जो हमें आकर्षित करती है।

किसी का मुखड़ा एक महत्त्वपूर्ण आयाम है जो व्यक्तित्व, भावनाओं और विचारों को दर्शाता है। चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियां और भावनाएं हमें आकर्षित करती हैं या फिर पीछे खींचने के लिए प्रेरित भी। चेहरे के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आंखें, मुस्कान और चेहरे की मांसपेशियों का तनाव, हमें व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। चेहरे पर दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। इसलिए किसी के मुखड़े को समझना बहुत मुश्किल और अहम है।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **य**ह एक प्रकार का प्रतीक हो सकता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने चेहरे पर एक और चेहरा बना सकते हैं! एक तरह से हम अपने चेहरे पर एक और चेहरा बना लेते हैं। अक्सर हम आवरण पहनते हैं या अपने चेहरे को सजाते हैं। मगर सवाल है कि क्या यह नया चेहरा हमारे असली चेहरे को छिपाता है या यह हमारे असली चेहरे का एक हिस्सा है?

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

निजता का अधिकार

हर नागरिक को निजता का अधिकार है। इसलिए आम लोगों के डेटा का संरक्षण सरकार का कर्तव्य है। आज के दौर में डेटा सुरक्षा एक अनिवार्य मुद्दा बन गया है। हमारी दैनिक दिनचर्या में आनलाइन गतिविधियों का दायरा बढ़ गया है। एक ओर इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हि बन चुका है। एक आम नागरिक से लेकर सरकार तक इसका इस्तेमाल कर रही है। अ बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है। दे वाट्सऐप, फेसबुक और एक्स सर्वाधिक लोकप्रिय मंच हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के एक विशाल ग्राहक आधार है। विदेशी कंपनियां डेटा संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं हैं। सरका स्वदेशी डिजिटल मंच विकसित करना चाहिए। कई बार लापरवाही के कारण भी डेटा की हो जाती है। इंटरनेट के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं। डेटा संरक्षण से संबंधित हमें अधि अधिक सुझाव सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। इस पर शीघ्रता से काम होना चाहिए।

- हिमांशु शेखर,

जोखिम में बच्चे

आज ज्यादातर बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन दिखता है। सोशल मीडिया के अनेक मंचों पर वे ऐसी सामग्री भी देखते हैं, जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। इस पर बंदिश लगाई जानी चाहिए। कम से कम किशोरों और बच्चों तक सोशल मीडिया की पहुंच रोकी जानी चाहिए। कानून बना कर अवांछित सामग्री पर लगाम लगाई जानी चाहिए। किसी भी चीज की अति, हमेशा दुष्परिणामों को जन्म देती है। आसानी से प्रयोग किया जाने वाला इंटरनेट बच्चों को चिड़चिड़ा और हिंसक बनाने के साथ अ रहने का आदी बना रहा है। ऐसे में ब जोखिम में हैं। इन परिस्थितियों में माता- के साथ सोशल मीडिया की भी जवाब बनती है कि अवांछित सामग्रियों के सुरक्षा कवच की पहल हो। भारत सर द्वारा 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ए का मसविदा तैयार करने की पहल दूर निर्णय है। इसके लिए रायशुमारी में ज्याद ज्यादा लोगों की भागीदारी करनी चाहिए।

- नरेश कानूनगो, दे

चुनावी बयार

मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रम का एलान करते हुए सभी राजनीतिक दलों को मर्यादा में रह कर चुनाव प्रचार करने के लिए कहा है। भाजपा ने इसका स्वागत किया तो 'आप' और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कुछ प्रश्नचिह्न लगाए। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 58 सीटें सामान्य हैं और 12 आरक्षित हैं। भाजपा पूरे दम-खम से आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के मुद्दा में दिख रही है। कांग्रेस भी अपना चुनावी अभियान शुरू करती दिखाई दे है। प्रधानमंत्री ने दो रैलियां कर भाजपा के में माहौल बनाने की कोशिश की है। ज आम आदमी पार्टी ने लगातार चु घोषणाओं के माध्यम से जनता को अपने में करने का प्रयास किया है। वहीं कभी पसेवर वोट पाने वाली पार्टी बहुजन स पार्टी चुनावी क्रिकोण का चौथा कोण बना लग गई है। मगर चुनाव हवा किसके प जाएगी, यह वक्त तय करेगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दि

अमर्यादित भाषा

सभी राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के लिए अमर्यादित भाष प्रयोग करते रहते हैं। इससे उनके दल के लिए भी संकट खड़ा हो जाता है। पि एक दशक से यह सिलसिला अधिक चल रहा है। दिल्ली में एक नेता ने दो प्रति महिला नेताओं के लिए अशोभनीय टिप्पणियां कीं। नारी शक्ति का सम्मान का दावा करने पार्टी का नेता जब ऐसा करता है, तो वह हैरान करने वाला होता है। ऐसे नेता समझते हैं कि तरह की टिप्पणियां उन्हें राजनीतिक लाभ पहुंचाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग मीडिया में के लिए ऐसी अशोभन टिप्पणी करते हैं। इनकी सभाओं में ऐसी ओछी भाषा पर तालियां तो सकती हैं, लेकिन उनका जनाधार नहीं बढ़ा सकती। हमारे देश और संस्कृति में नारी को पूजा रहा है। जब उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग होता है, तो सिर लज्जा से झुक जाता है।

- नरेन्द्र टोक,

दैनिक जागरण

क्रियान्वयन के अभाव में अच्छी से अच्छी योजना भी व्यर्थ है

आर्थिक अपराधी

वह स्वागतयोग्य तो है कि इंटरपोल की नई व्यवस्था के तहत वह जानने में आसानी होगी कि विदेश भागे आर्थिक अपराधियों ने कहां कितना धन छिपा रखा है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अवैध तरीके से अर्जित किए गए और विदेश भेजे गए इस काले धन को हासिल करने में भी आसानी होगी? बात तब बनेगी, जब इस धन को सरलता से हासिल करने की भी राह खुले और साथ ही संबंधित आर्थिक अपराधी को देश भी लाया जा सके। आर्थिक अपराधियों की ओर से विदेश में जमा किए गए धन का पता लगाने के लिए इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी करने की जो नई मुहिम शुरू की है, उसमें भारत भी भागीदार है। यह अच्छा है कि इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी कर दिया, लेकिन यह ध्यान रहे कि शराब कारोबारी विजय माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। यही स्थिति नीरव मोदी के सहयोगी मेहुल चोकसी की भी है। इनके अलावा भारत से भागे कुछ और आर्थिक अपराधी भी हैं। इनमें से कुछ के बारे में तो यह अनुमान लगा लिया गया है कि उन्होंने कितना धन विदेश भेजा, लेकिन अन्य के काले कारनामों की तह तक नहीं पहुंचा जा सका है।

जिस तरह भारत अपने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, उसी तरह अन्य देश भी। इसका कारण यह है कि इंटरपोल के हस्तक्षेप के बाद भी अनेक देश अपने यहां रह रहे दूसरे देशों के आर्थिक अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में आनाकानी करते हैं। दुर्भाग्य से इनमें पश्चिमी देश भी हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि विजय माल्या और नीरव मोदी आदि को ब्रिटेन से लाने में सफलता नहीं मिल पा रही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विश्व के प्रमुख देश आर्थिक अपराध से निपटने को हामी तो भरते रहते हैं, क्योंकि जब ऐसा करने की बारी आती है तो वे अपेक्षित सहयोग देने से इन्कार करते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि काला धन जमा करने की दृष्टि से सुरक्षित माने जाने वाले देश भी आर्थिक अपराधियों के प्रति कुल मिलाकर नरम रवैया ही अपनाए हुए हैं। इसी कारण भारत और अन्य देशों का काला धन वापस लाने का अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि इंटरपोल हो यह कह रहा है कि आर्थिक अपराधियों की ओर से दूसरे देशों में जमा की गई अधिकांश संपत्ति बरामद नहीं की जा सकी है। समस्या केवल यह नहीं कि प्रमुख देश दूसरे देशों से भागकर आए आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं करते। समस्या यह भी है कि वे उनके साथ-साथ आतंकियों को सौंपने के मामले में भी सकारात्मक रवैये का परिचय नहीं देते।

दुर्घटना से देर भली

बिहार और केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बहुतेरे उपाय कर रही है। हेलमेट से लेकर गति सीमा तक की जांच हो रही है। राष्ट्रीय उच्च पथों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक गति में चलने वाले वाहनों पर रोक लग सके। प्रयासों को देखें तो इस दिशा में प्रतिदिन कुछ न कुछ होता रहता है। इसके बाद भी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या केवल सरकारी प्रयासों से दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है? उत्तर है-नहीं। दुर्घटनाओं की प्रकृति को देखें तो पता चलेगा कि अत्यधिक गति सीमा इसका सबसे बड़ा कारण है।

> अत्यधिक गति सीमा सड़क दुर्घटनाओं के बड़े कारणों में से एक है

वह ऐसा विषय है, जिसपर नियंत्रण के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। सीधा हिसाब है कि आप तेज गति से वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना होगी। गाड़ी चलाने वाले से लेकर उसमें सवार तक उसके शिकार होंगे। इसमें जानें भी जा सकती हैं। जान बच भी गई तो अंग भंग निश्चित है। इससे बचने का साधारण सूत्र यह है कि गति सीमा पर हमेशा नियंत्रण रखें। जल्दबाज किस्म के वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए सड़क के किनारे बड़े-बड़े बोर्ड पर लिखे रहते हैं-दुर्घटना से देर भली। कहीं-कहीं भावनात्मक टिप्पणी भी दर्ज की जाती है-बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सरकार हाल के दिनों में कुछ और प्रयास करने जा रही है। स्कूली पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा के उपायों को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह अच्छी बात है। आज के छात्र, जब कल जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आएंगे, उन्हें याद यह रहेगा तो वाहन चलाने के समय सतर्कता बरतेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आज के स्कूली बच्चों के वयस्क होने की प्रतीक्षा करें। हमें आज से ही कम से कम गति सीमा पर नियंत्रण के बारे में गंभीर हो जाना चाहिए।

रिश्तों पर कायम संदेह के बादल

हर्ष वी. पंत

जस्टिन ट्रूडो की विदाई के बाद भी कनाडा के साथ संबंध सुधरने की आशा धुंधली ही दिखाई दे रही है

प्रतीक चक्रवर्ती

जस्टिन ट्रूडो और अधिक उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते थे। फजीहत से बचने के लिए उन्होंने अंततः कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी राजनीति और करियर पिछले कुछ समय से भटकाव का शिकार रहा। वह जिस दलदल में फंसते जा रहे थे, उससे निकलने की कोई राह भी नहीं दिख रही थी। न केवल उनकी पार्टी, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से द्वारा भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। एक दशक पहले तक वैश्विक मीडिया के दुलारे रहे व्यक्ति की अब अमेरिका के 51वें राज्य के गवर्नर के रूप में सार्वजनिक रूप से खिल्ली उड़ाया जाना किसी दिग्गज के पतन की ज्वलंत मिसाल है। ऐसे में, उनके इस्तीफे पर कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती तब तक वह कार्यभार संभाले रहेंगे। कनाडा की मौजूदा संसद का कार्यकाल 24 मार्च तक है। उसके बाद चुनाव होने हैं।

देखा जाए तो ट्रूडो की अधिकांश समस्याएं उनकी ही देन हैं। लंबे समय से सहयोगी रहीं उनकी उपप्रधानमंत्री क्रिस्टीया फ्रीलैंड ने जब दिसंबर में एकाएक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तभी तय हो गया था कि ट्रूडो के भी अपने पद पर गिने-चुने दिन ही शेष हैं। फ्रीलैंड ने त्यागपत्र देते हुए आरोप लगाया था कि कनाडाई वस्तुओं पर ट्रंप के 25 प्रतिशत के संभावित आयात शुल्क से उत्पन्न होने वाली चुनौती का तोड़ निकालने की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहे। इससे बने माहौल में न्यू डेमोक्रेट्स और ब्यूबेक नेशनलिस्ट पार्टी जैसे दलों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, जो लिबरल पार्टी को लंबे समय से सत्ता में बनाए हुई थीं। तथ्य यह भी है कि कंजरवेटिव जैसे मुख्य विपक्षी दल के प्रति पिछले कुछ समय से जनसमर्थन बढ़ता जा रहा था, जबकि ट्रूडो को लिबरल पार्टी के भविष्य पर एक ग्रहण के रूप में देखा जाने लगा था। सहयोगियों के रवैये में ही इसकी झलक दिखने लगी थी। जैसे अपने इस्तीफे में फ्रीलैंड ने ट्रूडो को उनकी 'राजनीतिक तिकड़मों' के लिए आड़े हाथों लिया था। फ्रीलैंड का आशय अधिकांश कमियों के लिए दो महीने की बिक्री कर छूट और 250 कनाडाई डालर जैसी पेशकश की ओर था। उन्होंने ट्रूडो के नेतृत्व के साथ जुड़ी बुनियादी खामियों को रेखांकित किया। एक नेता जो अपने देश में व्यापक बदलाव के वादे के साथ 2015 में सत्ता में आया, वह आखिर में राजनीतिक तिकड़मों का सहारा लेने पर विवश हो गया।

विश्व में कोविड महामारी ने जो असर दिखाया, उससे कनाडा भी अछूता नहीं रहा। इसके बाद अधिकांश कनाडाई लोगों को आर्थिक दुर्दशा का सामना करना पड़ा। बढ़ती बेरोजगारी एवं चढ़ती महंगाई के सिलसिले ने ट्रूडो में लोगों का भरोसा और घटा दिया। उनकी लोकप्रियता तेजी से घटने लगी, जिससे उनके संगी-साथियों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रंप की वापसी ट्रूडो के लिए बड़ा झटका रही। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ को लेकर उनके दबाव के चलते ही ट्रूडो इस्तीफे पर मजबूर हुए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, 'अगर कनाडा अमेरिका में अपना विलय कर ले तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स की दरें कम होंगी और रूसी एवं चीनी जहाजों के निरंतर मंडराते खतरे से भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।' ट्रंप के इस कथन ने ट्रूडो के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया।

भारत के साथ रिश्तों को तो ट्रूडो ने जबरदस्त आघात पहुंचाया। ट्रूडो के नेतृत्व में भारत को लेकर ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसके चलते भारतीय विदेश नीति प्रतिष्ठान में कनाडा को 'नए पाकिस्तान' के रूप में देखा जाने लगा। रिश्तों के रसातल में पहुंचाने के लिए ट्रूडो की करतूतों को अनेदखा नहीं किया जा सकता। यह ध्यान रहे कि दोनों देश बड़ी मुश्किल से कनिष्क बम हादसे, परमाणु चुनौतियों और शीत युद्धकालीन रणनीतिक असहमति के दौर से आगे बढ़ने में सफल हुए थे। 2006 से 2015 के बीच स्टीफन हार्पर के कार्यकाल में द्विपक्षीय रिश्तों की रंगत बदलती दिखी थी, लेकिन ट्रूडो के दौर में रिश्ते और बदरंग होते गए। अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए खालिस्तानी चरमपंथियों की खुशामद ने भारत-कनाडा रिश्तों को गंभीरता से लेने की उनकी क्षमता को संदिग्ध बना दिया। भारत को निशाना बनाकर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का उन्होंने अंतिम पैंतरा चला। जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा तो कनाडा में कुछ ही लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया। आखिरकार, निज्जर और अन्य चरमपंथियों को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को उनकी सरकार ही बार-बार खारिज करती आ रही थी। इसके साथ ही ट्रूडो सरकार ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की नफरती एवं हिंसक गतिविधियों पर भी आंखें मूंद रखी थीं। ट्रूडो और उनकी पार्टी का यह रवैया एक खास तबके और विशेष रूप से खालिस्तान समर्थकों को लुभाने पर ही केंद्रित रहा। इस मामले में भारत की चिंताओं को अनदेखा करना एवं सिख अलगाववाद को लेकर असंवेदनशील रवैये ने भी द्विपक्षीय रिश्तों में खटास बढ़ाने का काम किया।

ट्रूडो की विदाई के बाद दोनों के संबंधों में सुधार की हल्की सी उम्मीद जगी है। हल्की सी इसलिए, क्योंकि न केवल उनकी पार्टी के अन्य नेता, बल्कि विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे भी शायद ही खालिस्तानी चरमपंथियों के विरोध का साहस जुटा पाएं। कारण कि ऐसे तत्वों ने कनाडा के समाज और राजनीति में अपनी जड़ें गहराई से जमा ली हैं। इसलिए ट्रूडो के बाद जो भी सत्ता की कमान संभालेगा, वह अगर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना चाहे तो उसके लिए उसे अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दोनों देशों के संबंधों में एक दशक के दौरान हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

सुलझाना होगा एमएसपी का सवाल

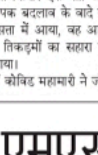

केसी त्यागी

किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए सरकार के लिए कुछ नए उपाय करने आवश्यक हो गए हैं

पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि में बदलाव के साथ किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे बातें की भी जरूरत जताई। कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की है। संसद के पटल पर रखी गई इस रपट में पीएम किसान सम्मान राशि को भी 6,000 से 12,000 रुपये करने की भी संस्तुति है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण सरकारों की चिंता बढ़ रही है। 2020 में मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानून लाने और फिर इन्हें खत्म करने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता था। किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून किसानों से अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं, बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टाक सीमा हटा ली गई थी।

कृषि कानूनों से किसानों में यह बात घर कर गई कि इनके जरिये सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों का मोहताज बनाकर छोड़ देगी, जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिये कृषि क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कृषि संकट एक वैश्विक घटना है। कई देशों में छोटे किसानों को संसाधनों तक पहुंच की कमी, कम पैदावार, अस्थिर बाजार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में इस कृषि संकट के चलते किसानों की आत्महत्या की घटनाएं 1970 से ही प्रारंभ हो गई थीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 1995 से 2014 के बीच 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की। 2014 से 2022 के बीच नौ वर्षों में यह संख्या 10,047 थी। नाबार्ड के अनुसार मौजूदा समय देश के सभी तरह के बैंकों का करीब 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यानी प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपये है।

किसानों से भेंट करते कृषि मंत्री शिवराज सिंह। एएनआइ

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार किसानों को जरूरी दर से कम एमएसपी देने से किसानों को लगभग 60 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके चलते किसान कर्ज में डूब गए हैं। यह किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। इसी असंतोष के चलते 2020 में किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ किसानों की मांगों पर सहमति बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही। कई दौर की मीटिंग के बाद भी आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का अता-पता नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमेटी के कुछ निष्कर्ष अवश्य प्रकाश में आए हैं, जिसके अनुसार किसानों की लागत और कृषि हेतु लिए गए कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। समिति ने उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए एमएसपी की कानूनी मान्यता सहित 11 मुद्दे चिह्नित किए हैं।

हाल में कृषि उत्पादकता में गिरावट, बढ़ती कृषि लागत, अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम और सिकुड़ते कृषि रोजगार से कृषि आय में गिरावट आई है। घटता जलस्तर, बार-बार सूखा पड़ना, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का पैटर्न, भीषण गर्मी आदि जलवायु आपदाएं भी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। किसान अपनी आजीविका को बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसी आर्थिक असुरक्षा के चलते पंजाब के किसान संगठनों ने स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार सभी फसलों पर एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एमएसपी को महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाना है। यह प्रणाली पांच दशकों से अधिक समय से चल रही है। सरकार की धारणा है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने से उसे सभी कृषि उपज खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, सभी कृषि उपज बाजार में नहीं आतीं। किसान कुछ उपज को स्वयं के उपभोग, बीज और पशु चारे के लिए बचाकर रखते हैं। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप केवल तभी तक आवश्यक होता है, जब किसी वस्तु का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है। इसीलिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने पर विचार होना चाहिए। एमएसपी की गारंटी न केवल किसानों की आत्महत्या को रोकने और महंगाई घटाने में सहायक होगी, बल्कि जल संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति को संरक्षित करने में भी मददगार होगी।

(लेखक पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

व्यक्तित्व का विकास

देव संस्कृति का स्थान विश्व की समस्त संस्कृतियों में सर्वोपरि रहा है। जहां के निवासी देवता हों उसे देव संस्कृति कहते हैं। उनके सोच, विचार, चिंतन, स्वभाव, कर्म सभी उच्चकोटि के होते हैं। उनका जीवन अनुशासन, आदर्श, मर्यादा एवं सिद्धांत से परिपूर्ण होता है। वे स्वार्थपरता एवं संकीर्णताओं से ऊपर होते हैं। जिस संस्कृति के लोगों में इन दिव्य गुणों का समावेश होता है, उसमें सुख, शांति, खुशी, उल्लास, आमोद-प्रमोद जैसे सुखद वातावरण का सृजन होता है। ऐसे परिवार, समाज, देश, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। लोगों का अंतःकरण हर्षित हो उठता है। अभाव में भी वे मिल-बांटकर खाते हैं। उन्हें जरा भी दुख, विषाद, संताप का अहसास नहीं होता, लेकिन जिस संस्कृति में लोगों में स्वार्थपरता, संकीर्णता, दुष्टता व्याप्त हो तो वहां दुख, अशांति, कलह-क्लेश, द्वंद्व का वातावरण बन जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को समय, धन, शक्ति, पद-प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होता है। अगर नींव कमजोर है तो उस पर खड़े भवन को धराशायी होते देर नहीं लगती। ऐसे ही व्यक्तित्व के खोखला होने पर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का पतन होते देर नहीं लगती।

लोग अच्छा घर बनाना, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किंतु अपने अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण पर ध्यान नहीं देते। जबकि सर्वप्रथम अपना व्यक्तित्व गढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन को सावधानी के साथ गढ़ता है, तभी वह बिक्री योग्य होता है। अपना व्यक्तित्व भी मनुष्य कुम्हार की भांति गढ़े। नैतिकता, चरित्र एवं चिंतन इसके प्रमुख आधार हैं। हर तरफ पतन का मुख्य कारण नैतिकता का अभाव है। नैतिकता का अभाव पशुता का प्रतीक है। व्यक्तित्व को सुंदर ढंग से नहीं गढ़ा तो मानव जीवन व्यर्थ है। जीवन का उत्थान व्यक्तित्व के निर्माण में है, जो देव संस्कृति का प्रमुख आधार है।

मुकेश ऋषि

बुजुर्गों के हितों की रक्षा

सुनीता मिश्रा

अगर बच्चे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं, तो उन्होंने बच्चों को जो भी संपत्ति दी है, उसे वापस ले सकते हैं

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि अगर बच्चे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते तो उनके नाम हस्तांतरित की गई संपत्ति वापस ली जा सकती है। अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे कई बुजुर्ग माता-पिता हैं, जिनके बच्चे संपत्ति लेने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उनके हाल पर छोड़ देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को बुजुर्गों की मदद के लिए बनाया गया है। अगर बच्चे देखभाल करने में विफल रहते हैं, तो बुजुर्ग माता-पिता ने उन्हें जो भी संपत्ति और उपहार दिए हैं वे कानून के तहत वापस लिए जा सकते हैं।

वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख एवं सुरक्षा के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 बनाया गया है। कानून की धारा 23 कहती है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति किसी को हस्तांतरित करता है कि वह उनकी सेवा करते हुए बुनियादी सुविधाएं देगा, लेकिन संपत्ति लेने वाला इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसे में संपत्ति का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति हासिल करने के बाद उनकी देखभाल करने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बुजुर्ग माता-पिता को वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ता है। यही कारण है कि आज भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारतीय संस्कृति में माता-पिता का सर्वोच्च स्थान है। हमारे समाज में बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई है। युवाओं को अकेले रहने की पश्चिमी जीवन शैली को त्यागना होगा और भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। उन्हें यह बात समझनी होगी कि एक परिवार की तरक्की में बुजुर्गों का बड़ा योगदान होता है। जहां बुजुर्ग संतुष्ट रहते हैं, वह परिवार हमेशा फलता-फूलता है। घर में बुजुर्गों के रहने से बच्चों के अलावा अन्य लोगों को भी सहारा रहता है। उनकी सूझबूझ से परिवार पर आने वाली हर मुश्किल दूर होती है। बुजुर्गों की सेवा चार धामों की यात्रा के समान है। इसलिए बच्चों को उनकी सेवा करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में उन्हें सभी सुविधाएं देनी चाहिए। उनकी सेवा करने से जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं उससे जीवन में उन्नति होती है। उनसे अलग रहकर कोई भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता है। जिस प्रकार बिना किसी संपत्ति का लालच किए माता-पिता कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का बहुत ही प्यार से पालन-पोषण करते हैं। उसी प्रकार बच्चों को भी बुजुर्गों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सरकारी स्कूलों का सुधरे स्तर

'खस्तहीन शिक्षा से पनपते कोचिंग केंद्र' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. विशेष गुप्ता ने ठीक ही कहा है कि सरकारी शिक्षण शिक्षण संस्थानों में खस्तहीन शिक्षा और भ्रष्टाचार के कारण छात्रों एवं अभिभावकों की रुचि कोचिंग संस्थानों एवं निजी शिक्षण संस्थानों में बढ़ रही है। दरअसल कोविड समय में अभिभावकों और युवाओं के मन में यह धारणा बन गई है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा बिना कोचिंग के उत्तीर्ण नहीं की जा सकती। मेरा मानना है कि देश में कोचिंग केंद्र इसीलिए पनप रहे हैं, क्योंकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी उनकी 'परीक्षा पद्धति' के अनुसार क्विश्चेशों से पढ़ाई कराते हैं और उसी पद्धति के अनुसार बार-बार टेस्ट आयोजित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई कोचिंग संस्थानों के छात्रों के परीक्षा परिणाम बेहतर आते हैं, जिससे उन संस्थानों का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाना है, तो सरकारों को भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोचिंग संस्थाओं में 'प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं' की तैयारी कराने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उसे अपनाना होगा। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारों को शिक्षकों को पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य गैर शिक्षण कार्यों से मुक्ति देना होगी, ताकि वे छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं के लिए जरूरी प्रशिक्षण दे सकें। सरकारी स्कूलों और कालेजों में सरकार द्वारा विवेकानंद करियर प्रकोष्ठ स्थापित किया जाता है। यदि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से छात्र-छात्राओं को परीक्षाओं के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा सके तो उन्हें कोचिंग की ओर नहीं भागना पड़ेगा।

डा. प्रदीप कुमार संघवी, शिक्षाविद्, सेवानिवृत्त प्राचार्य, झाबुआ (मध्य प्रदेश)

संपति सृजन जरूरी

प्रो. केशी सुब्रमण्यम ने 'संपति के सृजन को मिले सम्मान' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में भारतीय समाज में व्याप्त वर्तमान विचारधारा 'धनाढ्य समाज का धन अभावग्रस्त लोगों में बांट दिया जाए या कंपनियों पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए', का खंडन किया है। यह सही है कि रोजगार उपलब्ध कराने वाले नहीं हैं, तो संपूर्ण समाज अपने परिवार के लालन-पालन के लिए आर्थिक स्रोत कहां से खोजेगा। समाज में एक प्रतिशत लोग भी स्वयं के स्रोत के आधार पर स्वावलंबी नहीं हैं। आइएएस, आइपीएस, इंजीनियर, टेक्नोलाजी एक्सपर्ट, निर्माण कार्य में सहयोगी कामगार या घरेलू कार्यों में सहायक सभी को आर्थिक स्रोत वाले के साथ काम करना अनिवार्य है और जब तक कोई संपति सृजन नहीं करेगा तो वह किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहयोग नहीं कर सकता। लेख में वास्तविकता को उजागर किया गया है, साम्यवाद से पीड़ित व्यक्ति अवश्य इसका विरोध करेंगे। विदेशी विचारधारा साम्यवाद या समाजवाद के स्थान पर भारतीय विचारधारा 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।।' को अपनाएं। धरातल पर समाज की सही विवेचना करने के लिए लेखक का अभिनंदन करता हूं।

सुधीर गोयल, पिलखुवा

भव्य और दिव्य महाकुंभ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महाकुंभ के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डिजिटल महाकुंभ का प्रबंध करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने 'ग्रीन महाकुंभ' लक्ष्य को भी सामने रखा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया है। इस तरह से देखा जाए तो 2025 का महाकुंभ अभी तक हुए सुविधा के अनुसार सभी महाकुंभों में सबसे बढ़ा और व्यापक साबित होने वाला है। इस तरह से कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 को लेकर देश-दुनिया में उत्सुकता है और योगी सरकार बेजोड़ प्रबंधन के माध्यम से 2025 के महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाना चाहती है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****